SHRI NARESH GUJRAL (Punjab): Sir, this morning, we were assured that on the issue of attack which took place in a Gurudwara in America, we would be allowed to raise the matter. I don't want to stop the discussion on Assam. But we only want an assurance that tomorrow, during Zero Hour, we will be allowed to raise the issue.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): You can give the notice to the Chairman. Now, Punjji.

SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA:*

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P. J. KURIEN): No. Sit down. (*Interruptions*) What do you want? (*Interruptions*) After the discussion, the Government will say what it wants to say. Sit down. (*Interruptions*) Mr. Baishya, sit own. (*Interruptions*) Mr. Baishya, no more please. Mr. Punj.

SHORT DURATION DISCUSSION

Recent incidents of communal violence in Assam

श्री बलबीर पुंज (ओडिशा): उपसभाध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आज आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर सदन में बोलने का अवसर दिया। मैं जब इस विषय पर तैयारी कर रहा था, मैंने असम का इतिहास देखा, असम की इस समस्या का इतिहास देखा, इसके साथ जुड़े हुए बहुत सारे मानवीय पहलू देखे, इस समस्या का राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ क्या संबंध हो सकता है उसे देखा, असम के अंदर जो अभी हो रहा है उस बारे में देखा, तो मुझे लगा कि इतने वर्षों के लेखन के बाद भी मेरे पास उपयुक्त शब्द नहीं हैं, जिनसे कि हम असम की समस्या का, असम की इस त्रासदी, का, पीड़ा का वर्णन कर सकें। मेरी यह समस्या हल हुई, जब मैंने आज सबेरे का अखबार देखा। आज के समाचार पत्र में असम के मुख्य मंत्री तरुण गोगई जी का एक बयान छपा है, उनका वक्तव्य छपा है, जिसमें उन्होंने कहा है- "Assam is sitting on a volcano." अर्थात असम एक ज्वालामुखी पर बैठा है। इसे पढ़कर मुझे लगा कि जो अभी असम की त्रासदी है, वह कल को पूरे देश की त्रासदी बन सकती है और अगर उसको कोई शह दे सकता है तो ऐसा वक्तव्य दे सकता है कि असम जो है, आज ज्वालामुखी पर बैठा हुआ है।

उपसभाध्यक्ष जी, हमें एक बात ध्यान में रखनी चाहिए जब ज्वालामुखी फटता है तो जिस स्थान पर ज्वालामुखी होता है केवल वहीं स्थान प्रभावति नहीं होता है, बल्कि जब ज्वालामुखी फटता है तो उसकी आग आसपास के बहुत बड़े क्षेत्र को अपने लपेटे में ले लेती है और जब ज्वालामुखी फटता है तो उसका धूंआ और वहां से जो लावा निकलता है, वह पूरा का पूरा आसपास के बहुत बड़े क्षेत्र को प्रभावित करता है। इसलिए जब यह असम का ज्वालामुखी फटेगा, जिसका जिक्र वहां के मुख्य मंत्री जी ने किया, तो इसका प्रभाव केवल असम तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका प्रभाव पूरे देश की सुरक्षा, अस्तित्व, अस्मिता सम्मान, इस सब के ऊपर पड़ेगा। यह बात हमको ध्यान में रखनी चाहिए।

---

* Not recorded.

[श्री बलबीर पुंज]

उपसभाध्यक्ष जी, अभी हाल का जो घटनाक्रम हुआ, कल ही असम में तीन लोग और मारे गये हैं, सरकारी आंकड़ा तो कोई 70-75-76 के आसपास है, मगर जानने वाले लोग कहते हैं कि कई सौ लोग मारे गऐ हैं, सैकड़ों लोग घायल हुए हैं और चार लाख लोग अपने ही देश में, अपने ही घर में शरणार्थी हो गए हैं, रातों-रात उनकी जिंदगी बदल गई है। वे लोग जो आज शरणार्थी शिविरों में हैं, उनकी स्थिति बहुत दयनीय है। वहां शरणार्थियों को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है, उनके लिए भोजन की व्यवस्था नहीं है, मूलभूत मानवीय सुविधाएं उनको उपलब्ध नहीं हैं, शौचालय नहीं हैं, बीमारी है तो दवाइयां नहीं हैं। सबसे दुख की बात तो यह है, चूंकि असम सरकार को यह बताना है कि जो असम में जो हालात हैं वे ठीक हो गए हैं, इसलिए वहां लोगों को मजबूर किया जा रहा है कि वे 15 अगस्त से पहले अपने-अपने घरों को लौट जाएं। वहां पुलिस भेजी जा रही है।

उपसभाध्यक्ष जी, कोई अपना घर अपने आप नहीं छोड़ता। जब तक जान पर न बन जाए, अपना घर छोडकर कोई शरणार्थी कैम्प में नहीं जाता। जिनके घरों में आग लगी थी, उस आग की आंच भी अभी ठंडी नहीं हुई है और सरकार अपनी नाक बचाने के लिए उन शरणार्थियों को मजबूर कर रही है कि वे लोग अपने घरों को वापस लौट जाएं। मैं आपके माध्यम से केन्द्रीय सरकार और असम राज्य सरकार से यह मांग करता हूं कि जब तक शराणार्थी बिल्कुल सुरक्षित अनुभव न करें, जब तक उनके गांवों में सुरक्षा की व्यवस्था न हो जाए, तब तक किसी व्यक्ति को मजबूर करके उन्हें अपने गांव या अपने घर जाने के लिए नहीं कहना चाहिए।

उपसभाध्यक्ष जी, यह घटनाक्रम 19 जुलाई के आसपास शुरू हुआ, सच में देखा जाए तो असम में ऐसी छोटी-मोटी आग पहले से जलती रही है। दशकों से जल रही है, लेकिन जब यह घटनाक्रम शुरू हआ, तो एकदम से हिंसा की आग फैली। जब हिंसा की आग फैली, तो मुख्य मंत्री जी ने कहा कि उन्होंने सेना बुलाया था, लेकिन सेना समय पर नहीं आई। रक्षा मंत्रालय की ओर से कुछ और कहा गया। देश यह जानना चाहता है कि दंगा कब शुरू हुआ? राज्य सरकार की तरफ से कौन सी तिथि को यहां रक्षा मुत्रालय में यह आवेदन आया कि सेना को हालात ठीक करने के लिए भेजा जाए? रक्षा मंत्रालय ने प्रदेश सरकार की इस प्रार्थना पर विचार करने के लिए कितने घंटों या दिनों का समय लिया, यह स्पष्ट जानकारी भी दी जानी चाहिए। जब सेना को आदेश मिला, तो सेना ने आदेश मिलने के बाद स्थिति को संभालने में कितना समय लगाया, यह जानकारी भी सरकार की तरफ से दी जानी चाहिए। मेरी जानकारी के अनुसार रक्षा मंत्रालय, प्रदेश सरकार की प्रार्थना के ऊपर दो दिनों तक बैठा रहा। 24 जुलाई को सेना को आदेश दिया गया और 25 जुलाई को भारतीय सेना के सैनिक मोर्चा संभाले हुए थे, शांति स्थापति करने के लिए जो प्रयास करना चाहिए था, वह प्रयास उन्होंने किया।

उपसभाध्यक्ष जी, अगर सेना पहले भेजी जाती, तो क्या यह संभव नहीं था कि बहुत सारी जानें नहीं जाती, बहुत सारी संपत्ति नहीं जलाई जाती तथा बहुत सारे निर्दोष लोग घायल नहीं होते?

उपसभाध्यक्ष जी, पिछले सत्र में जब रक्षा मंत्रालय की मांगों पर सदन में बहस हो रही थी, तब मैंने इस बात की ओर सदन का और देश का ध्यान दिलाया था कि किन-किन क्षेत्रों में रक्षा के मामले में कमजोरी है। देश के अंदर की जो सुरक्षा है, नागरिकों जो जहां तक सुरक्षा देने का प्रश्न है, वह जिम्मेदारी देश की पुलिस और अर्धसैनिक बलों पर होती है। हमारे देश की सीमाओं की जिम्मेदारी भी अर्धसैनिक बलों के ऊपर है, BSF के ऊपर है, CRPF के ऊपर है, SSB के ऊपर है, ITBP के ऊपर है।

उपसभाध्यक्ष जी, देश में ये जो अर्धसैनिक बल हैं, इनकी क्या हालत है? आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पिछले 5 सालों में 50,000 से ज्यादा लोगों ने केन्द्रीय पुलिस बलों से त्यागपत्र दे दिया, उन्होंने नौकरी छोड़ दी है। 2011 में जितने लोगों ने नौकरी छोड़ी है, यदि इसकी हम तुलना करें, तो 2010 की तुलना में 70 परसेंट ज्यादा लोगों ने नौकरी छोड़ी है। जो CRPF के अधिकारी हैं, अनके लिए अनिवार्य सेवा अवधि होती है, लेकिन बहुत सारे अधिकरी ढाई से तीन लाख रुपए का जुर्माना देकर CRPF और अन्य अर्धसैनिक बलों को छोड़ रहे हैं। वे क्यों छोड़ रहे हैं? इसका एक बड़ा कारण यह है कि जिस तरह की political interference पुलिस के काम में की जाती है, उससे उनका मनोबल टूटता है। जब सुरक्षा बल देश के अन्दर आतंकवादियों से लोहा लेते हैं, तो बहुत से नेता वोट बैंक की खातिर सुरक्षा बलों का मनोबल तोड़ते हैं और आतंकवादियों के साथ खड़े हुए नजर आते हैं। दिल्ली के बाटला हाउस में इंस्पैक्टर शर्मा की शहादत हुई, हम सब यह जानते हैं, लेकिन सत्ताधारी दल के एक बड़े नेता ने उनकी शहादत को इज्जत नहीं दी और वे जाकर आतंकवादियों के साथ खड़े हो गए। अगर ऐसे मामलों में देश का नेतृत्व वोट बैंक की खातिर पुलिस अधिकारियों का मनोबल तोड़कर आतंकवादियों के साथ खड़ा होता है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि जैसी स्थिति का निर्माण असम में हुआ है, वहां पुलिस अधिकारी और अर्धसैनिक बल कितना काम कर पाएंगे?

उपसभाध्यक्ष महोदय, असम की समस्या बहुत पुरानी है। देखा जाए तो दिसम्बर, 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, उसके साथ ही इस समस्या का जन्म हुआ। कहीं न कहीं यह प्रयास हुआ कि असम को मुस्लिम बहल कर दिया जाए और उसके लिए तभी से लोगों ने कोशिश शुरू कर दी। 1931 में असम से सेंसस सुपरिंटेंडेंट, जो एक अंग्रेज थे, Shri C.S. Mullan–उन्होने अपनी फाइल में नोटिंग की–"The invasion of a vast herd of land hungry immigrants mostly Muslims from the District of East Bengal, particularly Maimansingha, they are invading the area." यह 1931 की बात है। उसके बाद 1937 में जब अंग्रेज़ो का राज था, पहली बार असम से चुनी हुई सरकार बनी। सर सैयद मोहम्मद सादुल्लाह उसके प्रधान मंत्री बने, उस वक्त मुख्य मंत्री नहीं कहा जाता था। असम और अन्य क्षेत्रों के जो चीफ मिनिस्टर होते थे, उनको "प्रीमियर" या "प्राइम मिनिस्टर" कहा जाता था। तो उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया और आंदोलन था "ग्रो मोर"। "ग्रो मोर" के लिए उन्होंने मेमनसिंह और आसपास के जो अन्य जिले थे, वहां से बड़ी संख्या में मुसलमानों को बुलाना शुरू किया और असम में बसाना शुरू किया। उससे जनसंख्या का जो अनुपात था, वह बदला, वह बिगड़ा और लॉर्ड वेवल, जो तब के वाइसराय थे, उन्होंने officially कहा कि "It is not a 'grow more compaign', it is a 'grow more Mohammadiancampaign'." और यह रिकॉर्ड पर है। मोहम्मद अली जिन्ना, जिनकी पाकिस्तान बनाने में विशेष भूमिका थी, जो वहां

[श्री बलबीर पुंज]

के पहले सदर भी थे, उनके पी.ए. मनुल हक चौधरी थे। उन्होंने भी असम में भारी संख्या में जनसंख्या का धार्मिक आधार पर, मज़हबी आधार पर बदलाव करने का प्रयास किया और वे पाकिस्तान नहीं गए। वे जिन्ना साहब की पूरी सहायता करते रहे कि पाकिस्तान का निर्माण हो, देश टूट जाए परंतु जब पाकिस्तान बना, तब वे पाकिस्तान नहीं गए और वे यहा इस सरकार में मंत्री बन गए। साथ ही एक दूसरे कांग्रेस के नेता * जो बाद में भारत के राष्ट्रपति भी बने, उनकी भी इस मामले में जबर्दस्त भूमिका थी।

उपसभाध्यक्ष महोदय, देवकांत बरुआ को...**(व्यवधान)**...

SHRI K. RAHMAN KHAN (Karnataka): I request that he should not take the name of the former President. ...(*Interruptions*)...

SHRI BHUBANESWAR KALITA (Assam): It is totally wrong. ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Are you yielding? ...(*Interruptions*)...

SHRI BALBIR PUNJ: No, I am not yielding. ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): He is not yielding. ...*(Interruptions)*.. He is not yielding. ...(*Interruptions*)... Kalitaji, he is not yielding. ...(*Interruptions*)...बैठिए....He says he is not yielding. (*Interruptions*)...

श्री बलबीर पुंज: उपसभाध्यक्ष जी....**(व्यवधान)**..

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P. J. KURIEN): When your chance comes, you can say that. ...(*Interruptions*).. You are going to speak...(*Interruptions*)...You can reply then. ...(*Interruptions*)... Why do you want to reply now? ...(*Interruptions*)..

श्री बलबीर पुंज: उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं कांग्रेस वालों का दर्द समझ सकता हूं परंतु हम भूल नहीं सकते, इन लोगों ने इस समस्या को पैदा करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है।...**(व्यवधान)**...आपके पूर्व अध्यक्ष देवकांत बरुआ...**(व्यवधान)**...जिन्होंने यह कहा था--India is Indira, Indira is India, उन्होंने एक स्टेटमेंट भी और दिया था, जो रिकॉर्ड में है और उन्होंने कहा था...**(व्यवधान)**...I am not yielding. ...(*Interruptions*)..They will have an opportunity to speak, Sir....(*Interruptions*)...I am not yielding....(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): I can't hear. ...(*Interruptions*)...

श्री बलबीर पुंज: उपसभाध्यक्ष जी....**(व्यवधान)**...

SHRI P. BHATTACHARYA (West Bengal): He is misleading the House. ...(*Interruptions*)... You kindly tell the hon. Member to correct himself and make a statement which is correct. What he is saying is a distorted one. ...(*Interruptions*)... He is distorting the things.

---

* Expunged as ordered by the Chair.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): You can reply. ...(*Interruptions*)... Do you want to say something?

SHRI K. RAHMAN KHAN: Sir, one minute. The name of a former President of India has been taken, which is not in good taste. I request that it may please be removed from the record.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Yes, yes, it is expunged. ... (*Interruptions*).. That is expunged. ...(*Interruptions*)...

SHRI BALBIR PUNJ: I am not referring to his role as President of India, but I am referring to his role as ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Please don't take the names of those who cannot come here and defend themselves. (*Interruptions*)... You please stick to the rules. Don't take the names of those who cannot come and defend here.

SHRI BALBIR PUNJ: Okay, Sir. Let me continue.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): You please stick to the rules. Don't take the names of those who cannot come and defend here. (*Interruptions*)...

SHRI BALBIR PUNJ: He became infamous for his statement during Emergency that 'India is Indira and Indira is India'. The same gentleman also made a statement, which I read, "Alis, that is, the marginalized Muslims, and *Kulis*, the migrant tea estate workers, would always keep the Congress alive...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): From where are you quoting? If you are quoting from a document, you must authenticate it. You can't simply say that you are quoting.

SHRI BALBIR PUNJ: Sir, everybody uses quotations. (*Interruptions*)... So, you created a situation जिसमें, जो जनसंख्या का अनुपात था, वह भयंकर रूप में बदला और उससे जो स्थानीय असमी लोग थे, उन लोगों में असुरक्षा भी भावना उत्पन्न हुई। उनमें असुरक्षा की भावना इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि जो लोग बाहर से आ रहे थे, जिनको वोट बैंक की खातिर बाहर से बुलाया जा रहा था, उनकी वजह से, उनकी सम्पत्ति, उनका सम्मान और उनका अस्तित्व, तीनों खतरे में पड़ गए थे। उसका परिणाम यह हुआ कि 70 के दशक में वहां एक बहुत बड़ा छात्र आंदोलन हुआ-ऑल असम स्टूडेंट यूनियन। उन्होंने मुख्यत: दो मागें कीं कि जितने बंगलादेशी हैं, उनको चिन्हित किया जाए और एक नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजंस बनाया जाए। उसके बाद 1979 में इलेक्शन हुआ, जिसका बहिष्कार करने के लिए कहा गया। उसमें केवल 10 प्रतिशत लोगों ने वोट दिया। उनके दम पर कांग्रेस ने सरकार बना ली। वे दस परसेंट वोट देने वाले कौन लोग थे, उनके बारे में अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। सर, उसका एक दुष्परिणाम हुआ कि 18 फरवरी 1983 को नैल्ली में, गुवाहाटी के पास...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Kalitaji, you will also get a chance to speak. Please sit down. (*Interruptions*)... You can speak when your chance comes. (*Interruptions*)... Renukaji, please sit down. (*Interruptions*)...

SHRI BALBIR PUNJ: Sir, I am not yielding. (*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): He is not yielding. रेणुका चौधरी जी, बैठिए।...**(व्यवधान)**...

SHRI BALBIR PUNJ: On 18th February, 1983, there was a genocide of Muslims at a place, called Nelli, very close to Guwahati. (*Interruptions*)...And, in 1985, the then Prime Minister, late Shri Rajiv Gandhi, entered into an Accord with the Assam students. The Accord, basically, had three points. उसके तीन बिन्दु थे। पहला यह था कि बंगलादेशियों को चिन्हित किया जाएगा, ढूंढा जाएगा, दूसरा एक नेशनल सिटिजन रजिस्टर बनाया जाएगा और तीसरा, जो असम की सीमा है, खास तौर से बंगलादेश के साथ लगती हुई जो सीमा है, उस सीमा के ऊपर प्रॉपर तारबंदी की जाएगी। उपसभाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के लोगों के द्वारा इस तरह से शोर मचाने से अच्छा है कि वे अपने अंतर्मन में झांकें। उनके नेता ने 15 अगस्त 1985 को लालकिले की प्राचीर से पूरे देश के और असम के लोगों के साथ वायदा किया था कि एक-एक बंगलादेशी को चिन्हित किया जाएगा और उन्हें देश से निकाला जएगा। उनके प्रधान मंत्री के उस वायदे का क्या हुआ, इस बात का उत्तर उनको देना पड़ेगा। क्या हुआ उस वायदे का?...**(व्यवधान)**...दूसरा, यह कहा गया कि फेंसिंग की जाएगी...**(व्यवधान)**...

SHRI BHUBANESWAR KALITA: Sir, I have a point of order.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P. J. KURIEN): Under what rule? (*Interruptions*)... You are the next speaker. Why are you interrupting? (*Interruptions*)... You are the next speaker. (*Interruptions*)...

SHRI BALBIR PUNJ: Elections were held after the 1985 Accord and the Assam Gana Parishad formed the Government. (*Interruptions*)... It was the duty of the Assam Government to implement that Accord. (*Interruptions*)

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P. J. KURIEN): You are the next speaker. Why are you interrupting him? (*Interruptions*)... This is not allowed. (*Interruptions*)...

श्री बलबीर पुंज: उन्होंने यह वायदा भी किया था कि तारबंदी की जाएगी। The promise was made from the ramparts of Red Fort in 1985.

Sir, you will be surprised to know that till 1992 nothing was done. Not even a single pillar was erected in order to give protection around Bangladesh and between Bangladesh and Assam. It started in 1992 और आज भी फेंसिंग का काम अधूरा है। डिप्टी चेयरमैन सर, असम की और बंगलोश की जो सीमा है, वह करीब 270 किलोमीटर है। उसमें 50 किलोमीटर का रास्ता जान-बूझकर इस तरह का छोड़ा गया है जिससे कि वहां के लोग बिना रोक-टोक के इस तरफ आ सकें और समस्या पैदा कर सकें।

डिप्टी चेयरमैन सर, यह कोई साम्प्रदायिक मामला नहीं है। यह कोई हिन्दू-मुसलमान का झगड़ा नहीं है। जिस तरह से सामने के लोग इसको हिन्दू और मुसलमान का झगड़ा बता रहे हैं।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Please address the Chair.

श्री बलबीर पुंज: ये जो झगड़ा है, यह मूलत: विदेश से आये हुए घुसपैठियों के बीच और यहां के स्थानीय लोगों के बीच का झगड़ा है। यहां के जो स्थानीय मुसलमान हैं, वे असम की पैदावार हैं, जिनका देश भारत है, उनको गोराया कहा जाता है और जो बंगलादेश से आते हैं, वे बंगाली भी नहीं बोलते, उनको मैमनसिंघी कहा जाता है और ये लोग समस्या पैदा करते हैं। इसलिए मेरी कांग्रेस से प्रार्थना है कि वह इस समस्या को साम्प्रदायिक ढ़ंग से न देखे। अगर देखना है, तो यह झगड़ा है विदेशियों द्वारा आक्रमण, इस देश की भूमि पर, यहां की सार्वभौमिकता पर, यहां के नागरिकों पर। यह जो समस्या है, यह इस तरह से बनी कि जनसंख्या को जो अनुपात था, वह बदलना शुरू हुआ। उपसभाध्यक्ष जी, कई जिलों के मेरे पास आंकड़े हैं, उन्हें मैं दे सकता हूं, जिससे पता लगता है कि किस तरह से स्थानीय लोगों के बीच में जनसंख्या का अनुपात बदला है। ये 8 जिले हैं और इसमें अलग-अलग तालुकाएं हैं। ये जनसंख्या के आंकड़े 1991 और 2001 के बीच के हैं, क्योंकि 2011 में जो सेंसस हुआ है, उसके आंकड़े अभी सार्वजनिक नहीं हुए हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इन तालुकाओं में हिन्दुओं की जनसंख्या का प्रतिशत निरंतर कम हो रहा है और मुसलमानों का प्रतिशत बढ़ रहा है। मुसलमानों की जनसंख्या इसलिए नहीं बढ़ रही है कि स्थानीय मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे है, बल्कि इसलिए बढ़ रही है कि बॉर्डर पार से, बंगलादेश से, मुसलमान as vote bank यहां पर बुलाये जा रहे हैं जिससे कि यहां के लोगों का अनुपात कम हो रहा है। कोकराझार में...**(व्यवधान)**...

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY (Andhra Pradesh): Sir, is this the level of debate?

SHRI BALBIR PUNJ: You are nobody to decide the level of the debate. ...(*Interruptions*)...You are not the yardstick...(*Interruptions*)... Please sit down. ..(*Interruptions*)... आप सुनिए।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Punjji, please address the Chair. ...(*Interruptions*)... Please address the Chair...(*Interruptions*)...रेणुका जी, आप बैठ जाइए।...**(व्यवधान)**...आप बैठ जाइए।...**(व्यवधान)**...

SHRI BALBIR PUNJ: Have patience to listen to...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Punjji, don't address them. Please address the Chair.

SHRI BALBIR PUNJ: So, Mr. Vice-Chairman, Sir, in Kokrajhar, in Gorgori, the share of Hindu population, between 1991 and 2001, dropped by one per cent and those of Muslims went up by almost 26 per cent. This happened because of

[Shri Balbir Punj]

infiltration. In Kokrajhar, again, in Dotma taluka, the share of Hindu population dropped by 16 per cent. There was a 16 per cent drop in the Hindu population, and the Muslim population rose by almost 26 per cent. In Dhubri, in Bagribari, the share of Hindu population dropped by -4.11 and that of Muslims went up by 31 per cent. In Chapar, again in Dhubri distrct, the rate of growth of Hindu population dropped by 2.17 per cent and that of Muslims went up by 37.39 per cent. Sir, I have a lot of figures. You have to go to the underlying causes of this unrest. If you just look at the symptoms and do not go into the real reasons, you will never be able to solve the problem. ..(*Interruptions*)..

SHRI BHUBANESWAR KALITA: Sir, he is quoting figures after figures. ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): You are the next speaker. You can reply in your turn. When you are speaking next, then why do you interrupt now?...(*Interruptions*)...No, No; it won't go on record. No, no. ...(*Interruptions*)...No, Kalitaji, no. You are the next speaker. ...(*Interruptions*)...

SHRI BHUBANESWAR KALITA:*

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): No, no, please. Not allowed. ...(*Interruptions*)...

श्री बलबीर पुंज: उपसभाध्यक्ष महोदय, कांग्रसियों ने एक तरह से घुसपैठियों को बुलाने का प्रबंध किया है, जो ये IMDT Act लेकर आए। सर, मेरे पास अधिक समय नहीं है जो मैं उसके अलग-अलग प्रोविजन बतलाऊं। IMDT Act का सीधा सा अर्थ यह है कि जो घुसपैठिया आ जाए, उसको सरकार का कोई अधिकारी वापस कर ही नहीं सकता। वह IMDT Act सुप्रीम कोर्ट के अंदर strike down हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने strike down करते हुए यह कहा कि 'This was an invisible invasion on India.' इस मामले में जो गुवाहाटी हाई कोर्ट ने कहा, मैं उसको पढ़ना चाहता हूं, "In a case involving as many as 61 people who had been found to be 'foreigners', the court said that most of them were able to avoid 'proceedings against them as well as their deportation from India' and that they have 'incorporated their names in the voter's lists on the basis of which they must have cast their votes". One of them with a Pakistani passport even contested the State Assembly elections in 1996. Gone further than any judicial opinion, so far, the court said, and I quote, "Large number of Bangladeshis in the State now play a major role in electing the representatives both to the Legislative Assembly and Parliament and consequently in the decision-making process towards building the nation." Not mincing words, the court described their political influence that of

* Not recorded.

kingmakers." उपसभाध्यक्ष महोदय, इनकी नीतियों का यह परिणाम हुआ कि हाई कोर्ट को भी यह कहना पड़ा कि असम में आपकी सरकार चुनी जाएगी तो उसमें विदेशी निश्चित करेंगे कि कौन सरकार में आएगा। विदेशी ही निश्चित करेंगे कि कौन सा कानून बनेगा और कोर्ट के शब्दों में विदेशियों की भूमिका किंग मेकर की होगी।

महोदय, मेरे पास आंकड़े तो और भी हैं, परन्तु समय नहीं है। मैं केवल दो बातें और कहना चाहता हूं। हमारे प्रधान मंत्री डा. मनमोहन सिंह जी असम गए थे और 300 करोड़ रुपए की राहत घोषित की। उन्होंने राहत में यह नहीं बताया कि राहत किसको दी जाएगी। अगर यह राहत का पैसा घुसपैठियों में बांटा जाता है तो उसके दो परिणाम होंगें, एक तो भारत सरकार घुसपैठियों को वैधता प्रदान करेगी और दूसरे जो बंगलादेशी घुसपैठिए सीमा के पार बैठे हैं, उनको सीधा निमंत्रण होगा कि आप एक बार यहां आ जाइए, भारत आपका रेड कारपेट के साथ स्वागत करेगी।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Only two minutes are remaining.

SHRI BALBIR PUNJ: Sir, I request you to please adjust the time which was taken by interruptions. ...(*Interruptions*)... Sir, I was very disappointed by the statement of the hon. Home Minister. He looked at the problem just as a law and order problem. Can anybody in his senses forget the context in which this entire violence took place? आप इसको लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम मानते हैं? उसके बाद इस तरह के platitude देना कि सभी कम्युनिटीज को मिलकर रहना चाहिए, यह कैसा भाषण हुआ? जो विदेशी घुसपैठिए हैं, स्थानीय लोगों के घरों पर कब्जा कर रहे हैं, उनकी भूमि पर कब्जा कर रहे हैं, उनके सम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं और उनकी पहचान के लिए खतरा बन गए हैं, उनको और भारत माता के पुत्रों को, एक स्तर पर रखना घुसपैठियों की मदद करना है। गृह मंत्री का जो बयान था, वह बहुत निंदाजनक था।

मैं अपनी बात बात खत्म करने पे पहले तीन-चार डिमांड्स रखना चाहता हूं। मैंने पहले भी निवेदन किया है कि घुसपैठिए पचास किलोमीटर के खुले बॉर्डर से आते हैं। महोदय, मेरा सरकार से निवेदन है कि वह वोट बैंक को छोड़े और जो साम्प्रदायिकता का चश्मा पहना हुआ है, उसको उतारकर समस्या को देखे।

उस समय, जैसाकि माननीय राजीव गांधी जी ने देश के साथ वादा किया था कि बॉर्डर की सीमा के ऊपर, जैसे पंजाब और कश्मीर के अंदर fencing हुई है, वहां पर भी तुरन्त पूरी की पूरी सीमा पर प्रॉपर fencing करवाएं और उसकी एक समय सीमा रखें।

दूसरा, इस देश में कोई नहीं जानता कि बंगलादेश से कितने घुसपैठिए आए हैं। इनकी संख्या करोड़ों में है। आज इन करोड़ों लोगों को देश के बाहर निकालना भी कठिन है, क्योंकि बंगलादेश इनको वापस नहीं लेगा। मेरा निवेदन है कि इन लोगों को Stateless person डिक्लेयर किया जाए। पहले इनको चिह्नित किया जाए, they should be identified first and then they should be declared as Stateless who have no right to vote and

[Shri Balbir Punj]

who have no right to own property. (*Time-bell rings*)...(*Interruptions*)...They should be disenfranchised. इनको Stateless person बनाया जाए। इसका एक precedent है। उपसभापति जी, जम्मू-कश्मीर के अंदर 1947 में पश्चिमी पंजाब से करीब 30 हजार परिवर **आए** थे। अब उनकी संख्या शायद 2.5 लाख के आस-पास हो गई है, लेकिन वे 60 साल से शरणार्थियों की हालत में जम्मू-कश्मीर में रहते हैं और किसी को प्रदेश के अंदर वोट देने का अधिकार नहीं है, किसी को संपत्ति अधिग्रहण करने का अधिकार नहीं है...**(व्यवधान)**...

श्री मोहम्मद शफ़ी (जम्मू और कश्मीर): उनको बाकायदा...**(व्यवधान)**...वोट देने का अधिकार ...**(व्यवधान)**...

†**جناب محمد شفیع:** ان کو باقاعدہ --(*مداخلت*)-- ووٹ دینے کا ادھیکار --(*مداخلت*)--

SHRI BALBIR PUNJ: Are they entitled to vote in Assembly?..(*Interruptions*)... आज तक साठ सालों में उनको अधिकार दिया नहीं है...**(व्यवधान)**...उनको संपत्ति की भी अधिकर नहीं है...**(व्यवधान)**...उनकी सुरक्षा नहीं है...**(व्यवधान)**...आप क्या बात करते हैं?...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Please conclude (*Time-bell rings*)....Please conclude. ...(*Interruptions*)... कन्क्लूड कीजिए...**(व्यवधान)**...

श्री मोहम्मद शफ़ी: आप क्या बात करते हैं?...**(व्यवधान)**...वे पंचायत में वोट डालते हैं...**(व्यवधान)**...

†**جناب محمد شفیع:** آپ کیا بات کرتے ہیں --(*مداخلت*)-- وہ پنچایت میں ووٹ ڈالتے ہیں --(*مداخلت*)--

श्री बलबीर पुंज: उपसभाध्यक्ष जी...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन): आप कन्क्लूड कीजिए...**(व्यवधान)**...

श्री अविनाश राय खन्ना (पंजाब): मुझे मालूम है...**(व्यवधान)**...आप लोग क्या गलत बात बोलते हैं..**(व्यवधान)**...

श्री तरुण विजय (उत्तराखण्ड): आप लोग जानते हैं..**(व्यवधान)**...आप जानते हुए भी अज्ञानता का परिचय क्यों दे रहे हैं?...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन): आप लोग बैठिए...**(व्यवधान)**...खन्ना जी, बैठिए...**(व्यवधान)**... Don't disturb. ...(*Interruptions*)... Please don't disturb. ...(*Interruptions*)... नाराज मत होइए, बैठिए...**(व्यवधान)**...

श्री बलबीर पुंज: उपसभापति जी, यदि भारत के अंदर...**(व्यवधान)**...इन 2.5 लाख लोगों को इस देश की नागरिकता लेने का अधिकार...**(व्यवधान)**...

श्री तरुण विजय: इसके खिलाफ काम किया...**(व्यवधान)**...उसके बाद भी बोलने की हिम्मत करते हो..

† Transliteration in Urdu script.

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन): तरुण विजय जी, बैठ जाइए...**(व्यवधान)**...जल्दी कन्क्लूड कीजिए...**(व्यवधान)**...This is wastage of time. ...(*Interruptions*)... That is not going on record. ...(*Interruptions*)...

श्री बलबीर पुंज: इन लोगों को Stateless person डिक्लेयर करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इनको यहां पर सम्पत्ति खरीदने का अधिकार नहीं होना चाहिए, जिन लोगों ने वोटर लिस्ट में अपना नाम लिखा रखा हैं ...(*Time-bell rings*) Just last point. ...(*Interruptions*)... They must be disenfranchised immediately. उसके बाद किसी स्कूल, कालेज में एडमिशन लेने का अधिकार नहीं होना चाहिए...**(व्यवधान)**...

श्री जय प्रकाश नारायण सिंह: *

श्री तरुण विजय: *

श्री बलबीर पुंज: उपसभापति जी, मैं यह अंतिम बात कह कर खत्म करता हूं।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Please conclude (*Time-bell rings*) ...(*Interruptions*)...

श्री बलबीर पुंज: अभी तक यह बोडो समस्या कही गई है, लेकिन यह बोडो की समस्या नहीं है, यह कोकराझार जिले की समस्या नहीं है, यह असम की समस्या नहीं है, यह पूरे देश की समस्या है। हमें यह रवैया रखना होगा कि जब किसी भी भारतवासी के ऊपर, चाहे वह बोडो हो, उसके ऊपर कोई विदेशी घुसपैठिया बंगलादेश से आकर हमला करता है तो वह उस व्यक्ति पर हमला नहीं है, वह पूरी भारत माता पर हमला है, पूरे राष्ट्र पर हमला है। अगर यह रवैया रखेंगे, तभी असम की समस्या का समाधान होगा। धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन): आप बैठ जाइए...**(व्यवधान)**...

SHRI BHUBANESWAR KALITA: Mr. Vice-Chairman, Sir, I am very much pained to listen to the speaker who has spoken before me. It is much more a serious situation than he is making it out to be.

What was his mission and what was his Motion here? Sir, he has said that this is not a communal issue. He has said that and everybody has heard him. And, what is the Motion? The Motion is, "The recent incidents of communal violence in Assam." In the Motion itself, which they have moved, they have stated that this is a communal violence. And, he is deviating in his speech and saying that this is not a communal issue; this is an issue between Indians and non-Indians. I think, this is what he meant to say.

Sir, I want to come to the main point now, where actually the recent happenings took place, where violence has occurred. Nobody can deny that. The

* Not recorded.

[Shri Bhubaneswar Kalita]

violence was in such a proportion that the entire country, the entire nation has shown so much of concern. But, today, the people are in distress there. What message do you want to send from this august House–to divide people, or, to unite people; to assuage the violence, or, to ...(*Interruptions*).

श्री जय प्रकाश नारायण सिंह (झारखण्ड): सर, ये जो कह रहे हैं...**(व्यवधान)**

श्री भुवनेश्वर कालिता: सुन लीजिए...**(व्यवधान)**...आप सुन लीजिए...**(व्यवधान)**

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Allow him to speak. ...(*Interruptions*).

श्री भुवनेश्वर कालिता: मैंने अभी शुरु भी नहीं किया और आपने बोलना भी शुरु कर दिया...**(व्यवधान)** आपने बोलना शुरु कर दिया...**(व्यवधान)** पहले अप मुझे बोलने दीजिए, उसके बाद आपको जो कहना है, कहिए। वाइस चेयरमैन साहब ने आपको कहा है। Sir, the situation was such that about 4,80,664 people became homeless. They took shelter in relief camps. Now, the number of homeless people has gone down. Many people have left the relief camps and they have gone back to their residences. Now, the number of homeless people has come down to 3,64,083. So, the situation is improving. People have started going from the relief camps to their own houses. So, we should help the State Administration. We should help the people of those areas to maintain peace, to propagate peace and harmony among different sections of people. That should be the aim of every political party. That should be the aim of every section of people.

Sir, there were about 340 relief camps, which have come down to 245 now. Sir, these relief camps are not of one community. There are relief camps of different communities, different religious groups. So, to try to divide the people in distress in terms of religion, in terms of different sections should not be our approach. Our approach in that part of the country should be....(*Interruptions*).

DR. CHANDAN MITRA: Sir,...(*Interruptions*).

SHRI BHUBANESWAR KALITA: No, I am not yielding.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): He is not yielding.

SHRI BHUBANESWAR KALITA: I am not yielding. Let me finish.

DR. CHANDAN MITRA (Madhya Pradesh): Sir, the Chief Minister of Assam has issued a statement saying that only genuine Indians...(*Interruptions*).

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): He is not yielding. So, you should wait....(*Interruptions*).

DR. CHANDAN MITRA: There are foreigners also staying in these camps.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): He is not yielding. So, what is the point in saying?

DR. CHANDAN MITRA: Sir, I want Mr. Kalita, who is a very senior leader, that he must also know the sentiment that no foreign national will be resettled.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): He has not yielded. Then, what is the point?

DR. CHANDAN MITRA: Sir, I have made my point. He has heard me... (*Interruptions*).. .to what his own Chief Minister has said.

SHRI BHUBANESWAR KALITA: Sir, then, let me go to the background which hon. Member has mentioned, that is, the agitation.

This agitation was against the foreigners by the students union, and, that agitation culminated into an Accord, which he has mentioned. The then Prime Minister, Shri Rajiv Gandhi, made a Peace Accord, and, after the Peace Accord, power was given to those students who were agitating and they came back. What was the Accord? Hon. Member has very rightly said that the Accord was for detection, deletion and deportation. It was detection, deletion and deportation. I will not distort facts. I will be on points, perfectly, on points.

SHRI BALBIR PUNJ: Kalita ji, just one minute. (*Interruptions*) Give me one minute. Give me one minute. (*Interruptions*)

SHRI BHUBANESWAR KALITA: You have not yielded. Let me finish. (*Intetruptions*)... You say whatever you want to say but after I finish my speech. Let me finish. I have not finished even the sentence. (*Interruptions*)... I have not finished even the sentence. Let me finish the sentence. (*Interruptions*)...

SHRI BALBIR PUNJ: Give me one minute. (*Interruptions*)...

SHRI BHUBANESWAR KALITA: No, no. You cannot disturb me like this. (*Interruptions*)...

SHRI BALBIR PUNJ: How many Bangladeshis have been detected, and, how many have been deported? Your leader, Mr. Rajiv Gandhi, promised in 1985 that Bangladeshis would be detected and deported. How many people have been detected and how many people have been deported? (*Interruptions*)...

SHRI BHUBANESWAR KALITA: The Accord was for detection, deletion and deportation, and, after the Accord, a new Government came into power with a

[Shri Bhubaneswar Kalita]

mandate. What was the mandate? The mandate was detection, deletion and deportation of any foreigner, if any, in that part of the country.

Sir, who led the Government? It was the students themselves. Some of the leaders are here today. They led the Government for five years. From 1985 to 1991, there was the Government of those people who led the movement, who signed the Peace Accord, and, their mandate was to detect, delete and deport.

Sir, there were other mandates, like border fencing to ensure that no further influx is there, which has been completed. Sir, we have discussed many a time... (*Interruptions*)...

SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA (Assam): Sir, one minute. (*Interruptions*)

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): You will be given a chance to speak. (*Interruptions*)...

SHRI BHUBANESWAR KALITA: I am not yielding. Let me finish. Sir, they cannot take my time. (*Interruptions*)... You will have your own time. I will not disturb you. You will have your own time. You can say whatever you like but let me finish first. This is my time. I cannot give you my time.

SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA: I do not want to take your time, but you do not try to mislead the House.

SHRI BHUBANESWAR KALITA: Sir, border fencing was their responsibility, preparation of the NRC was their responsibility...(*Interruptions*)...

SHRI KUMAR DEEPAK DAS (Assam): Sir, this is not...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Your chance will come. (*Interruptions*)... You will get your chance. (*Interruptions*)...

SHRI BHUBANESWAR KALITA: Sir, from 1985 to 1991, how many foreigners were detected?

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): You will have your chance. Why do you disturb now? You can reply.

SHRI BHUBANESWAR KALITA: How many foreigners were detected during 1985 to 1991? (*Interruptions*)

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Baishya ji, you will get your chance. Why do you want to trouble now? (*Interruptions*)

SHRI BHUBANESWAR KALITA: Sir, one hundred and seventy. ...(*Interruptions*)...

3.00 P.M.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): You can reply. I will give you time. You can reply at that time. (*Interruptions*)... What is the need to disturb now? Please. (*Interruptions*) Are you yielding to him?

SHRI BHUBANESWAR KALITA: I am not yielding. I am not yielding at all. (*Interruptions*)

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): He is not yielding. (*Interruptions*)...

SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA: But he has no right to mislead the House. (*Interruptions*)...

SHRI BHUBANESWAR KALITA: Their mandate was detection, deletion and deportation. (*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): You note down the points and reply. (*Interruptions*)...

SHRI BHUBANESWAR KALITA: But after signing of this Accord, from 1985 to 1991, how many foreigners were detected, and, how many foreigners were deported? Sir, I am sorry to say that their Government could detect only 170 people. (*Interruptions*)...

SHRI KUMAR DEEPAK DAS: Sir, he is not...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Mr. Kalita, you address the Chair. (*Interruptions*)...

SHRI BHUBANESWAR KALITA: That is the fact. (*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Kalita ji, you address the Chair. (*Interruptions*)...

SHRI BHUBANESWAR KALITA: You will have to face this...(*Interruptions*)... The people of my country will be listening as to what you are speaking in this House.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Mr. Kumar Deepak Das, please. ...(*Interruptions*)...Mr. Kumar Deepak Das, please...(*Interruptions*)...

SHRI BHUBANESWAR KALITA: Sir, the Accord was signed ...(*Interruptions*)... The Assam Gana Parishad Government came and it was that...(*Interruptions*)...

SHRI KUMAR DEEPAK DAS:*

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Mr. Kumar Deepak Das, please do not interrupt. ..(*Interruptions*).. That will not go on recorded. ...(*Interruptions*).. What he is saying will not go on record...(*Interruptions*)...Please sit down, Mr. Kumar Deepak Das...(*Interruptions*)...

SHRI BHUBANESWAR KALITA: Sir, I am very sorry to say ...(*Interruptions*)... I know why they are agitated...(*Interruptions*)... They could not do anything ...(*Interruptions*)...

SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA: Because you people did not. ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): You address the Chair, please. ...(*Interruptions*)...

SHRI BHUBANESWAR KALITA: Let me answer. ...(*Interruptions*)... Let me tell you about border fencing. ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Baishya ji, let him conclude. You will get the chance. ...(*Interruptions*)...

SHRI BHUBANESWAR KALITA: The Chief Minister of Assam wrote three letters to the then Home Minister. ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): You note down the points. You can reply when your turn comes. ...(*Interruptions*)...

SHRI BHUBANESWAR KALITA: ... and then made the fencing, made provisions for lights...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): You please address the Chair.

SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA: *

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): What Baishya ji says will not go on record. ...(*Interruptions*)... Now, only what Mr. Kalita says will go on record.

SHRI BHUBANESWAR KALITA: And now, they are talking about the infiltration, foreigners and deportation. They have no right to say all these things. They were in the Government...(*Interruptions*)...

DR. CHANDAN MITRA: Sir, they were in power...(*Interruptions*)...

---

* Not recorded.

SHRI BHUBANESWAR KALITA: They were in the Government ...(*Interruptions*)...They did not do anything...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): What is this? ..(*Interruptions*).. Please...(*Interruptions*)...What is this?

SHRI BHUBANESWAR KALITA: Sir, the NRC...(*Interruptions*)... The National Register of Citizens...(*Interruption*)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): No, please...(*Interruptions*)... Hon. Members, kindly note that this is a very very important discussion and each Member has to make his point. Please allow everyone to make his point. And, I would request the hon. Members from Assam to note down the points. You will get enough time to reply. I will give you more time.

DR. V. MAITREYAN (Tamil Nadu): Three minutes is not enough time, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): No, no, we will give more time. I can assure you that I will give you more time than that is allowed to you. But let us have a serious discussion. Please cooperate. The point is, if you interrupt like this, nobody will be able to...(*Interruptions*)...

SHRI BALBIR PUNJ: Sir, I want to...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Mr. Punj, you have made your points. Why do you want to stand up again? ...(*Interruptions*)...

SHRI BALBIRPUNJ: Sir, the IMDT Act...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): No, no. ...(*Interruptions*)... The rule is ...(*Interruptions*)... No, no, I am on my legs. ...(*Interruptions*)... I am on my legs. ...(*Interruptions*)... There is a traditional rule in this House that if an hon. Member is speaking and if you want to interrupt or say something or ask a question, he has to yield. If he is not yielding, the Chair is helpless. That is the rule. Therefore, if he is not yielding, you can't interrupt. You can make your point when your turn comes. I will give you time.

SHRI KUMAR DEEPAK DAS: Sir, he is diverting the issue.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): He is only making his point. ...(*interruptions*)... You note your points...(*Interruptions*)...

SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA: Sir, I am on a point of order.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Under what rule?

SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA: Sir, Mr. Kalita mentioned that those who signed the Assam Agreement, those who were the part of the Government, sitting in the House...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): If you are on a point of order, say the rule. Otherwise, you will not be allowed. ...(*Interruptions*)..

SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA: Sir, my argument is that ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): No, no, it is no point of order. ...(*Interruptions*)...

SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA: Sir, I am not taking his time. But he has no right at all to mislead the House...(*Interruptions*)...He misleads the House...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): You can reply to that when your chance comes. Now, please sit down. Your point of order is disallowed. Please, sit down. You can reply when your chance comes. ..(*Interruptions*).. No, no, your point of order is ruled out...(*Interruptions*)...Yes, Mr. Kalita, you please continue. ...(*Interruptions*)...No, no, your point of order is ruled out....(*Interruptions*)...

SHRI BHUBANESWAR KALITA: Sir, it is the responsibility of the Central Government...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Kalita ji, you address the Chair...(*Interruptions*)...Mr. Kalita, you look at the Chair and address the Chair. Why do you give them so much importance and talk to them only? You address the Chair.

SHRI BHUBANESWAR KALITA: Thank you, Sir. I appreciate that you have intervened. Whenever they say something irrelevant...(*Interruptions*)...

SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA:*

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): No, no, please. ...(*Interruptions*)... It will not go on record...(*Interruptions*)...What Baishya says will not go on record hereafter...(*Interruptions*)...

SHRI BHUBANESWAR KALITA: Sir, the hon. Member has very rightly mentioned about the border fencing. But they did not do anything about the border fencing when they were in power. Three letters of the Chief Minister ...(*Interruptions*)...

SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA:*

---

* Not recorded.

SHRI BHUBANESWAR KALITA: I am not asking you....(*Interruptions*)... Threes letters of the Chief Minister were not even replied by the then Home Minister of the BJP Government. Sir, the Accord was signed in 1985. And, updating of NRC has been taken up only now when the Congress Government is at the Centre, when the Congress Government is in the State.

You were not serious. Had you been serious, you would have updated the NRC in 1985 and afterwards...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Baishyaji, please cooperate.

SHRI BHUBANESWAR KALITA: When the Congress Party is in the Government at the Centre and the State, then only the updating of NRC has started and the work is going on.

Sir, the hon. Member diverted the issue, so I had to reply to these things now. Now, let me come to the main issue. What has happened there?

SHRI KUMAR DEEPAK DAS:*

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Shri Kumar Deepak Das, it won't go on record.

SHRI BHUBANESWAR KALITA: In Barpeta district. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Only what Mr. Kalita says will go on record.

SHRI BHUBANESWAR KALITA: Sir, I can't reply to them. ...(*Interruptions*)... I have no business to reply to them. ...(*Interruptions*)... They know that in these two districts the NRC updating is going on as pilot project. ...(*Interruptions*)...

SHRI KUMAR DEEPAK DAS:*

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): You will get the chance to speak. ...(*Interruptions*)... What do you want? ...(*Interruptions*)... Shri Kumar Deepak Das, you take your seat. It is not going on record. ...(*Interruptions*)...

SHRI BHUBANESWAR KALITA: Sir, they have diverted the issue. ...(*Interruptions*)... They are distorting the history; they are distorting the records; and they are even distorting the facts. This is known to every Indian. Sir, it is the Congress Government which is taking steps to contain violence there.

SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA:*

---

* Not recorded.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Baishyaji, don't force me to name you. This discussion is on Assam. You are equally or perhaps more interested in taking part in it. Then why do you interrupt? I am telling you from the Chair that I will give you enough time to refute or rebut any of his points.

PROF. RAM GOPAL YADAV (Uttar Pradesh): Sir, he is not interrupting. He is only a translating it.

SHRI BHUBANESWAR KALITA: Sir, let me come to the main issue as to how the entire trouble started. The trouble started in the first week of July when some incidents took place in Gossaigaon area of Assam. That was followed by another incident on July 19, 2012 when some miscreants attacked one community. Then on July 20, it was retaliated by another community and then large-scale violence in certain areas of the State started. Some people started setting their houses on fire by physically evicting them. When all this started, people had to go to relief camps to take shelter. The Central Government immediately took steps and had sent 15 companies of paramilitary forces there. ...(*Interruptions*)... And within four days, from 20th July to 24th July, violence was contained. On 24th, for one day, trains were stopped. Within one day, on 25th, train services were restored. These are the facts, which you are only distorting. ...(*Interruptions*)...

Sir, the people, who have taken shelter in relief camps, have started leaving them on their own. I have already told you that their number has reduced from around four lakh to around three lakh. The hon. Prime Minister has immediately visited the relief camps and reviewed the situation. Hon. Home Minister also immediately visited the area and reviewed the situation and whatever Central Forces were required had been sent. Even the officers have been transferred and new officers have beer put there, so that violence is immediately contained.

Sir, one or two incidents have happened recently on 5th and 6th and they also have come under control. Now, it is in the process. Peace is coming back. Peace process has started. Sir, I want to remind my hon. friends in the Opposition that they were in the Government. They have signed the Peace Accord in 2003. In 2003, they were in power. They signed the Peace Accord. To maintain that Peace Accord, to bring in peace, is their responsibility also. To bring in peace is the responsibility of the signatories of the Peace Accord, those who have signed the Accord. (*Interruptions*)

SHRI BALBIR PUNJ: You are the people who are disturbing peace. (*Interruptions*)

SHRI BHUBANESWAR KALITA: In 2003, you signed the Peace Accord, but

you are creating a situation of violence now. Let me tell you very frankly. You are talking about the people from one country or Bangladesh or whatever. You have said that. Let me answer it. This is not new. Violence has happened earlier also. Violence happened in 1993. Violence and attacks on each other happened, in 1993. It happened in 1994, 1996, 1998 and 2008. You want to say that these are foreigners and these are Bangladeshis. My hon. friend is trying to give it a colour of Indians and Bangladeshis. Let me ask him. Were the victims of clashes of 1996 and 1998 Bangladeshis? I am so sorry. Somebody said yes. It was a clash between a tribunal community with another tribunal community-Bodos and Adivasis. In 1996, Bodos and Adivasis; in 1998, Bodos and Adivasis. (*Interruptions*) Are the Adivasis foreigners? Are the Adivasis Bangladeshis? (*Interruptions*)

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Mr. Punj and Mr. Mitra, please. (*Interruptions*)

SHRI BHUBANESWAR KALITA: What have you to say? (*Interruptions*) We want to discuss the facts. (*Interruptions*) You go by the facts of what happened. (*Interruptions*) You want to divert the issue. (*Interruptions*)

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J.. KURIEN): You will get time to reply. (*Interruptions*)

SHRI BHUBANESWAR KALITA: You want to give a colour to the issue. (*Interruptions*) I am very sorry to say that you are inciting. (*Interruptions*)

DR. CHANDAN MITRA:*

SHRI BALBIR PUNJ:*

SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI (Gujarat):*

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Only what Mr. Kalita is speaking will go on record. (*Interruptions*). Nothing else other than what Mr. Kalita is speaking will go on record. (*Interruptions*) I don't allow you. (*Interruptions*) You will get time to reply. (*Interruptions*) Sit down. (*Interruptions*) You address the Chair.

SHRI BHUBANESWAR KALITA: My simple question is: Were the victims of 1996 clashes Bangladeshis? No.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Mr. Kalita, you have only two minutes. You have to conclude.

SHRI BHUBANESWAR KALITA: This is a problem of law and order. We must not forget that there is a problem of extremism, there is a problem of terrorism

* No recorded.

[Shri Bhubaneswar Kalita]

and there is a problem of militants. (*Interruptions*) You want to divert the issue by quoting Bangladeshis. My dear friends, let me remind you that, that part is not peaceful because there is militancy. Even now, there are, at least, three groups of militants who are active. You want to divert it as an issue of Bangladesh and India. I am very sorry. So many years have passed after signing of the Accord. (*Interruptions*) No, you want to score a political point. Please don't do that.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Mr. Punj, please. (*Interruptions*)

SHRI BHUBANESWAR KALITA: We all want peace in that part of the country. So, I appeal to you that please try to help bring peace in that part. Please don't divert issues. Please don't give communal colours because that will not help this country. It will not help in maintaining the unity and integrity of this country. The unity and integrity of the country is the main aim of the people of that area and the people of this country.

The people of that area want peace. We should give a message of national integrity, peace and harmony to that region. I appeal to my hon. friends in the Opposition to please help, please give a message of unity, integrity and social harmony to that place. Thank you very much.

श्री वीर सिंह (उत्तर प्रदेश): मान्यवर, आपने मुझे असम में जो जातीय हिंसा घटित हुई है, ऐसी ज्वलंत समस्या पर बोलने का अवसर दिया, मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूं। मान्यवर, असम में जातीय हिंसा में जो बहुत से लोगों की जानें गई हैं, यह एक बहुत दुखद और शर्मनाक घटना है। बहुजन समाज पार्टी इस घटना की निन्दा करती है। मान्यवर, आज स्वतन्त्र भारत में ऐसी जो जातीय दुखद घटनाएं हो रही हैं, यह बहुत ही चिंता का विषय है।

(उपभाध्यक्ष (श्री तारिक अनवर) पीठासीन हुए)

माननीय सदस्य ने असम की इस जातीय दुखद घटना को सदन में प्रस्तुत किया, जिस पर यह चर्चा हो रही है, मैं उनका भी धन्यवाद अदा करता हूं। मान्यवर, आज असम में जातीय हिंसा में जिन लोगों की मृत्यु हुई है, मैं केन्द्र सरकार से चाहूंगा कि वहां पर जो लोग मारे गए हैं, उनके आश्रितों को मुआवजा दिलाया जाए और जो बेघर हो गए हैं, उनको आवास प्रदान किया जाए। साथ ही उनको सुरक्षा प्रदान की जाए तथा भविष्य में ऐसी जातीय घटनाएं न हों, उस पर भी विचार किया जाए तथा गंभीरता से सोचा जाए, वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। मान्यवर, मैं बताना चाहूंगा कि हमारे देश के प्रधान मंत्री जी उसी प्रदेश से चुनकर आए हैं। इसलिए माननीय प्रधान मंत्री जी का भी दायित्व बनता है कि वे जिस प्रदेश से चुनकर आए हैं, वहां पर विशेष ध्यान दिया जाए। उसके साथ-साथ असम में कांग्रेस की सरकार है और यहां केन्द्र में भी आपकी सरकार है, दोनों सरकारो को मिलाकर असम में जो एक ज्वलंत समस्या है तथा वहां जातीय हिंसा हो रही है, उसको गंभीरता से लेना चाहिए। इस ओर माननीय प्रधान मंत्री जी का ज्यादा दायित्व बनता है।

मान्यवर, आपको बताना चाहूंगा कि देश में ऐसी जातीय हिंसाएं न हों, इसको रोकने के लिए बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर श्री कांशीराम जी ने पूरे देश में एक विशेष अभियान चलाया था। "जाति तोड़ो समाज जोड़ो" का नारा देकर मान्यवर श्री कांशीराम जी ने पूरे देश में ऐसा प्रयास किया था। उन्होंने कहा था कि जब तक ये जातिया नहीं तोड़ी जाएंगी तक तक ये हिंसाएं नहीं रुकेंगी। पूरे देश में कांशीराम जी ने यह अभियान चलाया था। मान्यवर, मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि भारतीय संविधान के निर्माता डा. भीमराव अम्बेडकर साहेब ने भी बहुत पहले एक नारा दिया था। क्या नारा दिया था कि भारत के अंदर समता मूलक समाज की स्थापना होनी चाहिए। समता मूलक का मतलब है, सर्व समाज में भाईचारा होना चाहिए। यह नारा बाबा साहब ने क्यों दिया था, क्योंकि उस समय हमारे देश में जात-पात के नाम पर बहुत बड़ी खाई थी, बहुत बड़ी नफरत थी। बाबा साहेब ने दूरगामी परिणामों को सोचते हुए कि हमारे देश में एक आपसी वैमनस्य है, जांत-पांत के नाम पर जो नफरत है, इसको कैसे दूर किया जाए, तब बाबा साहब ने यह नारा दिया था कि भातर के अंदर समता मूलक समाज की स्थापना होनी चाहिए।

समता-मूलक का मतलब है सर्व-समाज में भाईचारा होना चाहिए। आज इस नारे को साकार करने के लिए हमारी नेता, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्य मंत्री आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने बाबा साहब के इस नारे को सोचा और परखा। उन्होंने बाबा साहब के इस नारे को साकार करने के लिए आदरणीया बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश के शुरूआत की, सर्व-समाज मे भाईचारा कायम किया और वहां पूर्ण बहुमत की सरकार बनायी। आज बहन जी इस नारे को पूरे देश में पहुंचाना चाहती हैं। आदरणीय बहन मायावती जी बाबा साहब के इस नारे को साकार करने के लिए कटिबद्ध हैं।

महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि आदरणीय बहन मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में बाबा साहब के नारे को साकार कर दिया है। हम चाहते हैं कि असम के अंदर भी हमको ऐसा ही माहौल बनाना चाहिए और ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। मैं चाहूंगा कि पूरे देश में ऐसा माहौल बनाना चाहिए। मान्यवर, असम हमारे देश का सीमावर्ती प्रांत है। वहां पर ऐसा माहौल बनना बेहद जरूरी है। वहां का माहौल इतना खराब नहीं होने देना चाहिए जिससे कि समस्या पूरे देश में उत्पन्न हो जाए। मैं ज्यादा न कहते हुए केन्द्र सरकार से निवेदन करूंगा कि असम में जो जातीय हिंसा हुई, यह एक बहुत बड़ी शर्मनाक घटना है। उस ओर ध्यान दिया जाए, आश्रितों का पूरा ध्यान रखा जाए, उन्हें मुआवजा दिलाया जाए, उन्हें पूरी सुरक्षा प्रदान की जाए और वहां पर्याप्त फोर्स की व्यवस्था की जाए। हमें यह सुनने को मिला है कि वहां के माननीय मुख्य मंत्री जी ने सुरक्षा बल प्रदान करने के लिए कई बार केन्द्र सरकार को लिखा है, किन्तु उन्हें सुरक्षा प्रदान नहीं की जा रही है। यह दुख की विषय है जबकि सरकार दोनों जगह आपकी है-केन्द्र में भी और प्रदेश में भी आपकी सरकार है। इसलिए दोनों सरकारों को आपस में तालमेल बिठाकर असम की समस्या का समाधान करना चाहिए। जय भीम, जय भारत।

उपसभाध्यक्ष (श्री तारिक अनवर): धन्यवाद। श्रीमती झरना दास बैद्य।

श्रीमती झरना दास बैद्य (त्रिपुरा): थैंकयू सर। सर, असम का violence सम्पूर्ण ethnic

[श्रीमती झरना दास बैद्य]

violence है। हमारी पार्टी का delegation कोकराझार गया था। उसमें श्री बाजूबन रियान, बासुदेव आचार्य और एक लोकसभा के मेम्बर सईद-उल-हक शामिल थे। मैं भी नार्थ-ईस्ट में त्रिपुरा से आती हूं। पहले भी मैंने त्रिपुरा में ऐसे ही tribal and Bengali का violence देखा है, जोकि 1980 से शुरू होकर 2000 में खत्म हुआ था। हम लोग शांति से रह रहे हैं और उसके लिए लेफ्ट की गवर्नमेंट ने पूरी कोशिश की है। हम लोग देख रहे हैं कि असम में 1971 से यह शुरू हुआ और खत्म नहीं हुआ। यह खत्म क्यों नहीं होता है? गवर्नमेंट चाहे तो इसे खत्म कर सकती है। पहले वहां दो मुस्लिम peasants को मार डाला गया। वे unknown persons थे। उसके बाद दो स्टूडेंट्स को मार डाला गया। उसके बाद चार बोड़ो persons को मार डाला गया। फिर इसे लेकर दंगा शुरू हुआ। यह violence इसी वजह से हुआ है। बोडो लोग यह नहीं मानते कि बंगलादेश से आकर मुस्लिम्स ने यह violence किया। हमारी पार्टी भी यह नहीं मानती। ये मुस्लिम लोग बहुत सालों से असम में रह रहे हैं जोकि partition के बाद वहां नहीं गए। वे इंडिया में हैं, असम में हैं और जो लोग जो असम में हैं, उनका भी हक बताना है कि वे असम में रहें, इंडिया में रहें। वे इंडिया के सिटीजन हैं। तो वहां बोडो और ट्रायबल दोनों हैं।

ऑटोनामस डिस्ट्रिक्ट की मांग की। कांग्रेस पार्टी ने उस बोडो लिबरेशन टाइगर के साथ एलाइंस किया, तो यह डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी बना। अब वहां कुछ लोग चाहते हैं कि जो मुस्लिक अभी वहां रहते हैं, वे वहां से चले जाएं, वहां जो आइडेंटिफाइ एरिया है, काउंसिल एरिया है, उस एरिया में मुस्लिम लोग नहीं रह सकते। इस समस्या को कौन हल करेगा? हल तो गवर्नमेंट को करना चाहिए। बराबर हम लोग यह देखते रहे हैं, जब हमारी स्टेट में एनएलएफटी का डिस्टर्बेन्स था, उग्रपंथी का, तब जब इलेक्शन आया तो कांग्रस ने उसके साथ एलाइंस किया। उसके साथ एलाइंस करके फिर लेफ्ट की गवर्नमेंट को 1988 में हराया। इसके बाद क्या हुआ? यह समस्या खत्म नहीं हुई, लेकिन 1993 में लेफ्ट गवर्नमेंट आने के बाद से त्रिपुरा में आज शांति है। अगर गवर्नमेंट चाहे, तो समस्या का हल कर सकती है। असम में अभी इतने सारे लोग मारे गए, पांच लाख से ज्यादा लोग बेघर हुए, उनके घर जला दिए गए। इसके लिए गवर्नमेंट को पहले इस समस्या को देखना चाहिए, इस समस्या का हल निकालना चाहिए। आज वहां ऐसी स्थिति है कि लोगों के पास वहां खाने को नहीं है। हमारे डेलिगेशन ने देखा कि वहां जो वन का अनाज होता है, उसे बॉयल करके लोग खा रहे हैं। आखिर गवर्नमेंट क्या कर रही है? इस ओर उसे देखना चाहिए। लोगों को वहां सही ढंग से रिलीफ नहीं मिल रही है, उनको सही ढंग से सेटल करना चाहिए, जिनके लिए रीसेटलमेंट की जरूरत है। वहां जो रिवर है, जिसके पास लोग रहते थे अभी उस एरिया में वे लोग सेटल हुए, इसके लिए रीसेटलमेंट की जरूरत है। गवर्नमेंट रीसेटलमेंट भी नहीं कर रही। असम की समस्या तो त्रिपुरा की समस्या के भी बाद में आई। वहां ये लोग कुछ नहीं कर पा रहे, वहां भी उग्रपंथी हैं, सिक्युरिटी नहीं है। वहां पर असम की गवर्नमेंट सिक्युरिटी का भी प्रबंध नहीं कर सकती। क्या हो रहा है? वहां रिलीफ की जरूरत है, कंपनसेशन की जरूरत है, जो सरकार को देना चाहिए। आज वहां जो यह वॉयलेंस है, इस समस्या को पहले पॉलिटिकली देखना चाहिए। यह पोलिटिकली लीडर भी वहां पर शामिल हैं। हम लोगों ने देखा है कि पोलिटिकल लीडर किस तरीके से शामिल होते हैं? पॉलिटिकल इश्यू लेकर दंगा शुरू होता है, ऐसे नहीं होता है। दंगा हम लोगों ने देखा है, त्रिपुरा में हुआ है, लेकिन अब ऐसा नहीं है।

यह हमारी उपलब्धि है। इसी तरीके से असम गवर्नमेंट को भी करना चाहिए। ऐसा देखा गया है कि कोई बीजेपी को दोष देता है, कोई कांग्रेस को दोष देता है और जो अपोर्चुनिस्ट लीडर्स हैं वे चाहते हैं कि ऐसा चलता रहे।

सर, पहले भी इंडिया में दंगा हुआ, त्रिपुरा में हुआ, असम में हुआ, कई राज्यों में हुआ, लेकिन इस तरह का माइनॉरिटी-माइनॉरिटी दंगा कभी नहीं हुआ। इंडिया में मुस्लिम भी माइनॉरिटी है और बोडो ट्राइबल लोग जो हैं वे भी माइनोरिटी में हैं, माइनॉरिटी-माइनॉरिटी दंगा कभी नहीं हुआ है, हम लोगों ने त्रिपुरा में देखा है, मेजोरिटी-माइनॉरिटी का दंगा हुआ है, लेकिन माइनॅरिटी-माइनॉरिटी दंगा कभी नहीं हुआ। यह एक भयंकर संकेत है, क्योंकि हमारे देश की जो शांति है, जो संस्कृति है, जो समृद्धि है, उसके लिए यह एक भयंकर संकेत है माइनॉरिटी-माइनॉरिटी का दंगा होना, जो पूरे देश में हो सकता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी यहां मौजूद हैं, वे भी जानते हैं कि त्रिपुरा की सिचुएशन पहले कैसी थी, आज तो त्रिपुरा में शांति है, ऐसे ही असम में भी शांति होनी चाहिए। यह नॉर्थ-ईस्ट की सबसे बड़ी स्टेट है, इसलिए उस स्टेट की समस्या की ओर ध्यान देना चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट और असम स्टेट गवर्नमेंट, दोनों को मिलकर इस समस्या का हल निकालना चाहिए। धन्यवाद।

श्री शिवानन्द तिवारी (बिहार): उपसभाध्यक्ष जी, असम की घटनाओं के बारे में जैसा अभी श्री बलबीर पुंज जी ने बताया कि यह बहुत बड़ी human tragedy है कि एक हफ्ते के दौरान 4 लाख लोगों का internal immigration हुआ। यह कोई साधरण घटना नहीं है कि 4 लाख लोग रिफ्यूजी कैम्पो में हैं। अभी कालिता जी बता रहे थे कि इन रिफ्यूजी कैम्पों में रहने वालों की तादाद धीरे-धीरे कम हो रही है, लोग स्वत: अपने घरों की ओर वापस जा रहे हैं। यह स्वागत की बात है और यह सदन चाहेगा कि यथाशीघ्र ये रिफ्यूजी कैम्प खाली हो जाएं और लोग अपने-अपने घरों को लौट जाएं, ऐसी परिस्थिति असम में कायम होनी चाहिए।

उपसभाध्यक्ष जी, असम की जो समस्या है, उसके साथ मेरी भी थोड़ी-बहुत वाक्फियत है। उसका कारण यह है कि जब 1979 में "आसू" के लोगों ने बंगला देश की घुसपैठ के खिलाफ वहां आंदोलन किया था, उसी दरम्यान वैली में बड़ा भारी दंगा हुआ था, उसी दौरान हम लोहिया विचार मंच में काम कर रहे थे, उसकी ओर से हमने दिल्ली से गोहाटी तक एक साइकिल मार्च किया था। यहीं राजघाट से वह साइकिल मार्च शुरू हुआ था और उस साइकिल मार्च में सबसे उम्रदराज़ आदमी हम थे। हमारे साथियों ने कहा कि चलिए, आप हमको हरियाणा के बॉर्डर तक पहुंचा दीजिए। इसी में हम कानपुर तक साइकिल चलाते हुए चले गए और उसके बाद बिहार में पूर्णिया से हमने साइकिल पकड़ी और बक्सीहाट का बॉर्डर पार करके धुबरी जिले में हम लोग गए और वहां हम लोगों की गिरफ्तारी हुई। इस गिरफ्तारी के दौरान हमने देखा कि वहां कई तरह के contradictions हैं, कई तरह के अंतर्विरोध हैं। हमने वहां देखा कि जो असमी लोग हैं और जो बंगाली लोग हैं, हम बंगाली मुसलमान नहीं कह रहे हैं, हम बंगाली हिन्दू कह रहे हैं, उसके बीच भी भारी contradictions हैं। हम लोगों की गिरफ्तारी हुई, थाने में हम लोगों को ले जाया गया, वहां का इंस्पैक्टर बंगाली था, उसने चप्पल खुलवाई, बैल्ट खुलवाई, ऐसी सख्त तलाशी ली कि बिहार आंदोलन में और एमरजेंसी के दौरान भी उस तरह से पुलिस ने कभी हम लोगों के साथ सख्ती नहीं की थी और हम लोगों को बंद कर दिया। अगले दिन धुबरी में हम लोगों की मजिस्ट्रेट के यहां पेशी

[श्री शिवानन्द तिवारी]

हुई। वह मजिस्ट्रेट असमी था और उसने technical grounds पर हम लोगों को छोड़ दिया। अगले दिन फिर गिरफ्तारी हुई। इस तरह यह सिलसिला तीन दिनों तक चला और उसके बाद हम लोगों को असम से बाहर निकाल दिया गया। तब हमें यह अहसास हुआ कि यहां मामला सिर्फ असमी लोग, बंगाली मुसलमान या घुसपैठियों के बीच में नहीं है, यहां अनेक तरह से अंतर्विरोध है।

अभी बलबीर पुंज जी बता रहे थे कि ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और उसके बाद असम में जो demography है, उसको बदलने की कार्यवाही शुरू हुई। मै इस तर्क के साथ सहमत नहीं हूं। यह सही बात है कि 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और उसके बाद Minto-Marley Reforms आए, उनमें मुसलमानों के लिए अलग election college बनाने की व्यवस्था की गई, वह एक अलग बात है, लेकिन उस समय हिंदुस्तान और पाकिस्तान, दो अलग मुल्क बनेंगे, ऐसी कोई स्थिति नहीं थी। "संडे गार्जियन" एक अखबार निकलता है, उसमें श्री राम जेठमलानी जी का एक लेख परसों छपा था और उसमें उन्होंने बहुत साफ तौर पर कहा था कि मुसलमानों के बंगला देश से असम में जाने का जो सिलसिला शुरू हुआ, वह 1905 से शुरू हुआ, यह उन्होंने ठीक लिखा है, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि यह सिलसिला कहां तक पहुंचा? उनके लेख को पढ़ने के बाद हमने डिटेल्स देखीं कि 1911 में बंगाल से असम एक अलग राज्य बना था। आप देखिए कि 1911 में असम में मुसलमानों की आबादी 9 प्रतिशत थी और उस समय मुसलमानों की संख्या 3,65,540 थी, लेकिन 1921 में जनगणना में यह आबादी 5,94,000 हो गई, यानी लगभग 6 लाख हो गई, यानी दुगुनी आबादी हो गई। इसी तरह 1931 में यह आबादी साढ़े नौ लाख हो गई।

वहां 19 परसेंट की आबादी हो गई। आप देखिए, 1941 में लगभग 16 लाख 9 हजार यानी 17 लाख की आबादी हो गई और 23 परसेंट पॉपुलेशन बढ़ गई। बंगलादेश के मुसलमान असम में भारी संख्या में गए। उनको किसने बुलाया? मुस्लिम लीग ने उनको यहां नहीं भेजा। असम में आप देखिए, वहां कोयले का भंडार मिला। असम में चाय की खेती शुरू हुई। असम में पेट्रोलियम मिला और वहां काम करने वाले मजदूरों की जरूरत थी। बंगल में जो बड़े-बड़े जमींदार थे, भद्र लोग थे, वे हिंदू थे और मुसममान वहां मजदूर थे। उन्हीं गरीब मुसलमानों को अंग्रेजों ने वहां बसाना शरू किया। वहां खेती में भी मजदूरों की जरूरत थी। आप देखिए कि वहां जो माइग्रेशन हुआ है, वह केवल बंगलादेश के मुसलमानों का नहीं हुआ है। हमारे यहां बिहार का जो आदिवासी इलाका है, जो झारखंड का इलाका है, चाईबासा है, सिंहभूम है, मानभूम है, बीरभूम है, इन इलाकों में बड़े पैमाने पर आदिवासियों का माइग्रेशन उस इलाके में हुआ है। आप सेंसस की रिपोर्ट उठाकर देख सकते हैं। और तो और, आप नेपालियों की आबादी देखेंगे तो पता चलेगा कि 1911 में वे केवल कुछ हजार थे और 1941 में उनकी आबादी लगभग पांच-छ: लाख बढ़ गई। तो यह जो conflict है, conflict सिर्फ इसी हालत में नहीं है। आज वहां जो हालत है, अभी एक मैडम बोल रही थीं, असम की रहने वाली हैं, उन्होंने ठीक ही कहा। अभी दो-तीन दिन पहले एक अखबार "दैनिक भास्कर" के फ्रंट पेज पर एक स्टोरी छपी थी। 2003 में Bodo Liberation Tigers के साथ आपका समझौता हुआ और उन्होंने Bodo Territorial Council बनाई। उस Territorial Council के चेयरमैन अभी कौन हैं? मोहिलारी साहब उसके चेयरमैन हैं, जिनकी बहुत कम उम्र है। 1993 से लेकर 2003 तक

उग्रवाद की जितनी भी घटनाएं असम में हुई, जितना भी कत्लेआम हुआ, उसमें इनकी जमात, जो Liberation Tigers के नाम से जानी जाती थी, उसका हाथ रहा है। आज वहां क्या स्थिति है? यह जो Territorial Council बनी हुई है, वह वहां चीफ मिनिस्टर से ज्यादा पावरफुल है। सिक्योरिटी की करीब 25-30 गाड़िया उनके आगे-पीछे चलती हैं। इसके अलावा प्राइवेट सिक्योरिटी है और उनका क्या मकसद है-दैनिक भास्कर ने छापा है, उन्होंने उनसे पूछा। वहां बैनर लगे हुए हैं कि "असम को हम कश्मीर नहीं बनने देंगे। कश्मीर में हमारे हिंदू नौजवान मारे जा रहे हैं, इसमें में हम वैसी स्थिति पैदा नहीं होने देंगे।" वहां मोहिलारी से पूछा, तो मोहिलारी का किसके साथ संबंध है? आपकी पार्टी के साथ? कांग्रेस पार्टी के साथ? 2006 में जब वहां चुनाव हुआ, उस समय कांग्रेस को वहां बहुमत नहीं मिला, जबकि मोहिलारी की पार्टी को 12 असेम्बली सीटें मिलीं और इन्हीं के समर्थन से वहां कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी और उनको आपने खुला छोड़ा हुआ है? उनका संकल्प है कि जो कोकराझार इलाका है, इसमें मुसलमानों को वे नहीं रहने देंगे।...**(व्यवधान)**...आप देखिए...**(व्यवधान)**...

श्री बिश्वजीत दैमारी (असम): "दैनिक भास्कर" में छपे हुए के बारे में आप जो बता रहे हैं, यह सब गलत है। मैं...**(व्यवधान)**...

श्री साबिर अली: आप बाद में बोलिएगा...**(व्यवधान)**...

श्री बिश्वजीत दैमारी: बोलने दीजिए। आप किसी अखार में छपी बात को यहां क्यों बोल रहे हैं? आप क्या जानते हैं? वहां हम लोग कैसे रहते हैं, आपको पता है क्या?...**(व्यवधान)**... मैं कोई इसके विरोध में नहीं बोल रहा हूं।...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री तारिक अनवर): बिश्वजीत जी.....बिश्वजीत जी...**(व्यवधान)**...प्लीज....Your name is there in the List of Speakers. You can clarify it at that time. प्लीज, आपका नाम जब आए, तब बोलिएगा। आपको जिस बात पर आपत्ति हो, आप अपने समय में उसका जवाब दे सकते हैं।

श्री शिवानन्द तिवारी: मैंने जो कुछ कहा, वह अपनी ओर से नहीं कहा। मैंने एक अखबार का नाम लिया और वह अखार मेरे यहां नियमित रूप से आता है। इस खबर के साथ contradiction उस अखबार में नहीं छपा है।...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री तारिक अनवर): तिवारी जी, आपका समय खत्म हो रहा है, please conclude now.

श्री शिवानन्द तिवारी: इसलिए मैं मानकर चल रहा हूं कि इस अखबार में जो खबर छपी है, वह सही खबर है। मैं आपको बता रहा था कि किस तरह से पूर्वी बंगाल के इलाके से गरीब peasants आए, व आकर कहां बसे? उनमें अधिकांश लोग Goalpara डिस्ट्रिक्ट में बसे। Goalpara डिस्ट्रिक्ट का एक सब-डिविजन कोकराझार है। जहां यह Tribal Council बनी है, उसकी राजधानी कोकराझार है।

उसमें एक सब डिविजन था। उसी इलाके में अधिकांश मुसलमान आकर बसे। आज ग्वालपाड़ा कई जिलों में बंट गया है।

उपसभाध्यक्ष (श्री तारिक अनवर): तिवारी जी, अब समाप्त करिए।

श्री शिवानन्द तिवारी: सर, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। अंत में, मैं केवल एक उदाहरण देना चाहता हूं। अभी 2011 का जो सेंसस हुआ है, उस सेंसस की बाजाप्ता रिपोर्ट नहीं आयी है, लेकिन उसकी जो प्रोविजनल रिपोर्ट आयी है, उस प्रोविजनल रिपोर्ट के हिसाब से 2001 और 2011 के बीच में कोकराझार की जो मुस्लिम आबादी है, वह घटकर 5.9 प्रतिशत हो गयी है। सन् 2001 में जो आबादी 20.4 प्रतिशत थी, वह घटकर 5.9 प्रतिशत पर आ गई है, कोकराझार में 9 प्रतिशत मुसलमान घट गए हैं। क्यों घट गए हैं? जैसा मैंने आपको बताया कि वहां जो ट्राइबल काउंसिल बनी है, उस ट्राइवल काउंसिल के जो चेयरमैन हैं, उनका जो संकल्प है, यह उस संकल्प का परिणाम है कि वहां से मुसलमान हट रहे हैं। भाग रहे हैं। यहां उल्टी बात हो रही है। जहां दंगा हो रहा है, उस दंगे का कारण मुस्लिम आबादी का बढ़ना नहीं है। वहां की मुस्लिम आबादी उल्टे घट रही है। महोदय, प्रधान मंत्री जी यहां मौजुद हैं। मैं उनसे विनम्र अनुरोध करूंगा कि बंगलादेशियों का इस देश में आना एक तथ्य है। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं हैं कि बंगलादेशियों की घुसपैठ हो रही है। बंगलादेश एक गरीब इलाका है। आप देखिएगा कि अमेरिका में कई अगल-बगल के गरीब लोग infiltrate कर रहे हैं। हमारे देश से भी लोग वहां जाते हैं। सर, मुझे एक बार जापान जाने का अवसर मिला था। हालांकि मुझे विदेश जाने का शौक नहीं है, लेकिन सन् 1977 में एक बार मुझे चन्द्रशेखर जी ने जापान भेज दिया था। वहां मैंने देखा कि हमारी जो जापानी दुभाषिया थी, उसके साथ टैक्सी ड्राइवर भिड़ गया। जापान का जो समाज है वह अद्भुत किस्म का समाज है, वहां पर लोग बहुत शिष्टाचार मेंटेन करते हैं। हमने उस लड़की से पूछा कि वह कौन है? तब उसने बताया कि थाइलैंड वगैरह के लोग, जो मंगोलियन चेहरे वाले लोग होते हैं, व गरीब लोगा यहां infiltrate कर जाते हैं। उसने कहा कि जापानी ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता है। इस प्रकार हर जगह ऐसी हालत है कि जो गरीब इलाका है, उस इलाके से, थोड़ी-बहुत जहां समृद्धि है, वहां लोग आ जाते हैं। जहां दाल-रोटी नहीं मिल रही है, वहां से दाल-रोटी की उम्मीद में लोग ऐसी जगहों पर जाते हैं। हमारे यहां की क्या हालत हो गयी है? इससे तनाव पैदा होता है। यही तनाव असम में पैदा हुआ है। ऐसा केवल असम में नहीं है। बिहारी लोग जो असम में गए हैं वहां मारे गए हैं-रवि शंकर प्रसाद जी यहां बैठे हैं, इनको मालूम होगा। मुम्बई में हमारे यहां से, बिहार के लोग जाते हैं, उनके खिलाफ दंगा होता है। इस प्रकार आबादी का जो असंतुलन है, जो विकास नीति चल रही है, उसके चलते बेरोजगारी पैदा हो रही है। असमी आदमी को लगता है कि बाहर से आने वाला हमारा हक छीन रहा है। इसलिए प्रधान मंत्री जी से हम अनुरोध करेंगे कि...**(व्यवधान)**...

श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य: असमी people के बारे में आपने गलत बताया है...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री तारिक अनवर): जब आपको मौका मिलेगा, तब अपनी बात कहिएगा।

श्री शिवानन्द तिवारी: हमसे अगर कोई त्रुटि हुई हो तो आप सुधार दीजिएगा। ...**(व्यवधान)**...

श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य: असमी people के बारे में आपने जो कहा, वह गलत है।...**(व्यवधान)**...Don't treat the Assamese people in this way.

उपसभाध्यक्ष (श्री तारिक अनवर): वैश्य जी, आपको मौका मिलेगा। तिवारी जी, आपका समय समाप्त हो गया है...**(व्यवधान)**...तिवारी जी, आप चेयर को एड्रेस करें।

श्री शिवानन्द तिवारी: प्रधान मंत्री जी यहां मौजूद हैं। मैं यह कहूंगा कि इस समस्या को लेकर देश में तनाव पैदा हो रहा है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। इसलिए इस समस्या के समाधान के लिए जो भी उपाय संभव हों, सिटिजनशिप कानून में संशोधन की जरूरत हो, बंगलादेश बॉर्डर में जो फेंसिंग बाकी रह गयी है, जिसके बारे में श्री बलबीर पुंज जी बता रहे थे कि 50 किलोमीटर बाकी रह गया है, उससे बंगलादेश के लोग आ रहे हैं, उसको पूरा किया जाए यह सब करना जरूरी है। जो घटना हुई है, वह दुर्भाग्यपूर्ण है, उसकी हम निन्दा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि असम की सरकार, इस मामले में जो सिचुएशन है, उसके हिसाब से राइज़ करेगी और वहां शांति स्थापित करेगी। जो लोग गांव-घर से बाहर बिखरे हैं वे बोडो भी हैं और मुसलमान भी हैं। ऐसा नहीं है कि बोडोलैंड के खिलाफ खाली मुसलमान ही बाहर से आए हैं, दोनों कम्युनिटीज़ के लोग बाहर आए हैं। सर दंगे की जो शुरुआत हुई, उसमें सबसे पहले जो मुस्लिम ऑरग्नाइज़ेशन हैं उसी के नौजवान मारे गए थे। इस प्रकार दोनों कम्युनिटीज़ के लोग हैं, जो रिफ्यूजी कैंप में आए हैं। वे बिलकुल अमानवीय हालत में रह रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि वे सब अपने घरों में लौटें, ऐसी स्थिति असम की सरकार उत्पन्न करेगी। मैं यह भी उम्मीद करूंगा कि इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए प्रधान मंत्री जी पहल करेंगे क्योंकि वे इस सभा में उसी राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। धन्यवाद।

SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA: Vice-Chairman, Sir, just one minute, please.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TARIQ ANWAR): No, no. You will get your time. (*Interruptions*) Don't interrupt. अपका नाम है।

श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य: हम लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हमें बोलने का मौका नहीं मिल रहा।...**(व्यवधान)**... We are the mover of this Resolution and we were assured that we would be given the opportunity. But when will we get the opportunity? We are from Assam. We should be allowed to speak first. We are the mover of the Resolution.

उपसभाध्यक्ष (श्री तारिक अनवर): चेयर ने आपको assure किया है। The Chairman has assured you that you will get the opportunity. Don't worry.

SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA: When will we get the opportunity, Sir?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TARIQ ANWAR): Very soon. Now, Shri Md. Nadimul Haque.

श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य: सर, आप क्या कर रहे हैं? आपने सब लोगों को बोलने का मौका दिया है, हम लोगों को बोलने का मौका नहीं देते हैं।...**(व्यवधान)**...

श्री रवि शंकर प्रसाद (बिहार): सर, माननीय सदस्य असम से हैं, इनको बोलने का मौका पहले दे दीजिए।

SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA: Sir, you should not go by big party or small party. That is not the issue today.

उपसभाध्यक्ष (श्री तारिक अनवर): अगर हाउस agree करेगा, तो हम उनको बोलने के लिए मौका देने के लिए तैयार हैं। जिनका नाम पहले से है, जो बड़ी पार्टियां हैं, अगर वे agree करती हैं, तो हम उन्हें बोलने का मौका दे सकते हैं।

SHRI MD. NADIMUL HAQUE (West Bengal): Sir, let him speak.

उपसभाध्यक्ष (श्री तारिक अनवर): अगर हाउस तैयार है, तो मैं इन्हें बोलने का समय दे देता हूं। ठीक है। मो. नदीमुल हक साहब, क्या आप इनके बाद में बोलेंगे, जैसा आप कहें। वैश्य साहब, आप बोलिए।

SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA: Sir, thank you very much. I am standing here today to discuss in the interest of sovereignty and integrity of the country. I am thankful to my fellow colleague who has sacrificed his turn to me.

Sir, I am standing here today to speak in the interest of sovereignty, security and integrity of the country. I am not here to speak in favour of the vote bank. Our appeal to the people of this country is to save Assam today for a safe India of tomorrow. Today, Assam is burning. Here, foreign national proble is not between Hindus and Muslims. Here, it is a fight between indigenous people and the foreign infiltrators. This is the issue. Please do not try to...

SHRI BHUBANESWAR KALITA: Sir, I would like to respond.

SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA: Mr. Kalita, I have not disturbed you; allow me to speak. (*Interruptions*)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TARIQ ANWAR): Kalitaji, he is not yielding, please sit down.

SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA: Mr. Vice-Chairman, Sir, I need your protection. Today, Assam is burning. More than one hundred people are killed in Assam. More than five lakh people have become homeless. They have taken shelter either on the National Highways or schools and colleges. School and college areas are serving them as shelter for the last several days.

Sir, Shri Kalita, in his speech said that the situation was getting normal since the people in relief camps started going back to their own homes. Shri Kalita should know one thing. When the hon. Home Minister visited those affected areas, the people who were in the relief camps categorically asked the Home Minister to give them security and that only then would they go back to their homes. This is the real picture of my State. (*Interruptions*)

Sir, I am just beginning. What is this? In his speech, Shri Kalita said many things. Sir, it is time not to blame anybody; it is time to make peace and make Assam peaceful. Our appeal to everybody is not to shift the blame on another. Try to work hard to make peace and bring people together in our State. Assam burning means India burning.

Sir, what is the problem? We should know the reality. Today, by sending the Paramilitary Forces or the Army, you can solve the problem temporarily. It will not be a permanent one. In order to get a permanent solution, permanent measures are required. In his speech, Shri Kalita, pointing to us, said that the people sitting here got the power in 1985. Really, we got the power after educating the people of Assam; then, the people elected us and we formed the Government in Assam. It was not at the mercy of you, Mr. Kalita, but with the help of the people of the State. You just said that you gave power to us.

Sir, he said... (*Interruptions*)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TARIQ ANWAR): Mr. Kalita, you speak when your turn comes.

SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA: Sir, his turn is already over. When he spoke, we did not disturb him. At that time, he said, 'When your turn will come, then you speak.' Now, my turn has come, and now allow me to speak.

Sir, in the year 1985, the Assam Accord was signed between the then Prime Minister Rajiv Gandhiji and the leaders of the Assam Movement. What is the spirit of the Assam Accord? The spirit of the Assam Accord was to detect and deport the foreigners from Assam; number one. Number two, to fence the Indo-Bangladesh Border. Number three, to safeguard the indigenous people of the State of Assam. And also, according to the Assam Accord, the National Register will be updated. Mr. Kalita, in his speech, said, 'After coming to power, you people have not done anything.' Mr. Kalita, being a senior leader, I would like to mention here that the nodal Ministry was not the Assam Government; the nodal Ministry was the Union Home Ministry. To implement the Assam Accord, the nodal Ministry was the Union Home Ministry. It is not our responsibility. It is the responsibility of the Union Home Ministry. And by not implementing this Accord, you not only insult us, but you insult your own leader Rajiv Gandhiji also. It is because the nodal Ministry for implementing this Accord was the Union Home Ministry. Yes, we got power after the Assam Accord. Mr. Kalita, you should remember one thing. When we assumed the power, all the time, your party tried to communalize the issue between Hindus and Muslims. But I would like to inform you that when the AGP Government was in

[Shri Birendra Prasad Baishya]

power, not a single of such incident happened in Assam. Everybody should remember one thing. After the demolition of the Babri Masjid, there were clashes between Hindus and Muslims in different parts of India. Hindus took Muslims' blood and Muslims took Hindus' blood. But not a single incident occurred in Assam. It was because at that time Assam was ruled by the Assom Gana Parishad, my party, Sir.

Mr. Kalita, you should remember those days. At that time, Shri P.V. Narasimha Rao Government was at the Centre and AGP Government was in Assam. There was a bloodshed in many parts of the country after the demolition of the Babri Masjid. But not a single incident occurred in my State because, at that time, Assam was ruled by AGP; not your party, Mr. Kalita. Mr. Kalita, you do not forget about the implementation of the Assam Accord. When you were speaking about the Assam Accord...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TARIQ ANWAR): Please address the Chair. (*Interruptions*) You are addressing Shri Kalita!

SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA: Mr. Vice-Chairman, Sir, I do agree with you. But what he said during the course of his speech, I have to give him the reply.

Secondly, do not forget about the IMDT Act. Assam is a part of India. Can the people imagine that there is a separate law in Assam to deal with the foreigners? In other parts of the country, there is a separate Act to deal with the foreigners, and to deal with foreigners in Assam, there is a separate Act, which is the gift of your Government. Do not forget it. When we got power in Assam, we had requested for withdrawing the IMDT Act. Although an assurance was given by the then Prime Minister, Shri Rajiv Gandhiji for withdrawing the IMDT Act, your Government did not withdraw it. At last, the hon. Supreme Court helped us when it scrapped the illegal Act in Assam. So, you should take the responsibility. The people are speaking of updating of the National Register. Yes, we need updating of the National Register. In the interest of sovereignty of our country, in the interest of the security of our country and in the interest of the integrity of our country, the National Registration of the Citizens should be updated. But I am very sorry to say that at the initiative of the Union Home Ministry, there are two pilot projects for updation of National Register in Assam; one in Chaigaon and another in Barpeta district. But, later, in the name of communal clashes, upgradation of NRCs in Assam was stopped by the State Government. So, the Government of assam is not willing to update the National Register of Citizen certificate, Sir. We should know the reality. Okay, for immediate solution, we need more armed forces there to make Assam peaceful. Definitely, the Central Government is going to do its job by sending more Army to those areas.

It is a welcome move, Sir. But all these are temporary measures. We need a permanent solution. What is the permanent solution, Sir? Sincerity and reality are required. I would like to tell Kalita Sahib and my other colleagues that without sincerity you cannot solve this problem. Try to realize the situation, please. What is the real situation, what is the main problem, try to understand that. Without understanding this thing, you cannot solve this problem. The main problem which is still there is Indo-Bangladesh border and always infiltration is taking place from Bangladesh into Assam. Assam is a transit camp for extremist groups; Assam is a transit camp for Huji Jehadi groups who take shelter in Bangladesh. They come to Assam and after unlawful activities they go to Bangladesh because Indo-Bangladesh border is still open. It is the responsibility of the Union Home Ministry to seal the Indo-Bangladesh border. It was not the responsibility of the AGP Government, it was not the responsibility of the other Governments which ruled Assam but it was the responsibility of the Union Home Ministry to seal the Indo-Bangladesh border. I would like to mention here one very pity thing. The hon. Home Minister a few months back has given one order to our Border Security Force and what is the order–people will be surprised–if any Bangladeshi infiltrator comes to Assam, don't shoot them, don't use bullet against them. That was the instruction of the Union Home Ministry. So, for a permanent solution, sincerity is required and without sincerity you cannot solve the problem. Please try to understand the problem. Don't do anything in the interest of vote bank; try to do something in the interest of integrity, sovereignty and security of the country. Do not compromise for vote bank; for vote bank don't compromise with the sovereignty of the country. You people are going to compromise with the sovereignty in the interest of vote bank. We are not against the Muslims; we are not against any community, we are not against any Indian community, we are totally against the illegal foreigners who came to Assam through the open Indo-Bangladesh border.

(**THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN)** in the Chair)

Without solving this problem, such types of problems may continue to happen. Secondly, I would like to mention here that the real issue is Indo-Bangladesh border. Sir, 27 years have passed when Assam Accord was signed in 1985. Who signed the Assam Accord? it was signed by the then Prime Minister, Rajiv Gandhiji along with the leaders of Assam. One of the main issues of the Accord was that the Central Government may immediately seal the Indo-.Bangladesh border. Even after 27 years when the Accord was signed, till today Indo-Bangladesh border remain open. So, anybody can come to Assam from Bangladesh easily. So, it is my request to the hon. Prime Minister to do something in this regard. He was also very kind enough to visit the victims. He visited the affected people. But the reality

4.00 P.M.

[Shri Birendra Prasad Baishya]

is that you try to give a permanent solution. Temporarily you can solve this problem but it will not help. I suggest two things, one, short-terms measures and, two, the long-term measures. What are the short term measures? One short term measure is that you think about those five lakh people who took shelter in the relief camps. I am very sorry to say that in the relief camps people were killed. In relief camps also these people were killed. Who have got shelter in the relief camps, they are also not getting any safeguards and they are also suffering. Due to shortage of food, due to shortage of drinking water, due to shortage of medicines, many people died in the relief camps. (*Time-bell-rings*) Thirdly, Sir, I have one more thing to say. People still want more forces. People wants that they should be secure. The schools and colleges of those areas are closed. The people are in the relief camps. My request is that the Government should respond immediately, they should send more forces to those areas for bringing back peace and harmony in this area. (*Time-bell-rings*) The Central Government should send a medical team to affected areas, to relief camps with adequate medicines to save these people in the relief camps. Thirdly, they should arrange sufficient food and sufficient drinking water facilities in the relief camps.

And, what should be the long-term measures to find a permanent solution to the problem? To find a permanent solution, the Government should forget everything else, forget about the vote-bank, votes are not so important. Think about the sovereignty, integrity and security of the country. (*Time-bell-rings*) Kindly seal the Indo-Bangladesh border immediately. Identify the foreigners immediately. (*Interruptions*)....Save Assam today, to save India tomorrow, otherwise same situation will emerge in every part of the country. Don't think that only Assam is suffering, but the entire country will suffer. This is my warning to everybody. So, please try to solve this problem. Please don't try to see this problem either in the name of Hindus or in the name of Muslims. Please solve this problem on humanitarian grounds. My appeal to each and every Member of this House is that please try to evolve a permanent solution to make permanent peace in my State, Assam.

SHRI BHUBANESWAR KALITA: Sir, during his speech, he has taken my name several times. So, I have a right to clarify the situation. (*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Now, Shri Nadimul Haque. (*Interruptions*)...

SHRI BHUBANESWAR KALITA: Sir, he has taken my name several times. (*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): No; no. That was during the course of speech. (*Interruptions*)... Has he made any allegations against you? (*Interruptions*)... No; no. You are not allowed. (*Interruptions*)... You are not allowed. (*Interruptions*)...Shri Nadimul Hague. (*Interruptions*)... You are not allowed. (Interruptions)... Please sit down. (*Interruptions*)... I have not allowed you. (Interruptions)... What is this? (*Interruptions*)... I have not allowed you. (Interruptions)... You cannot reply. (*Interruptions*)... You are not supposed to reply. (Interruptions)... If there is any allegation or any derogatory remarks against you, I will go through the records and, then, I will allow you to explain your situation; otherwise, I can't allow you. Now, Mr. Haque.

श्री मो. नदीमुल हक (पश्चिमी बंगाल): एक-दो जगह नहीं, सारा बदन ज़ख्मी है, दर्द वेचारा परेशां है कि किधर से उठे।

वाइस चेयरमैन सर, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे मेडन स्पीच देने की इजाजत दी गई है।...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): I will go through the record. Please don't worry.

श्री मो. नदीमुल हक: असम का तशद्दुद बहुत बड़ा सामाजिक तसादुम है। हां, वहां बोडो मारे गये हैं, हां, वहां मुसलमान मारे गये हैं, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि वहां इन्सान मारे गये हैं और इन्सानियत रुसवा-ओ-गारत हुई है। एक शेर यहां अर्ज़ करता हूं--

जंग मशरिक़ में हो या मग़रिब में,
नस्ले आदम का खून होता है

मज़लूम इन्सानों पर ज़ुल्म हो रहा है और इंतज़ामिया की ख़ामोशी पर आपकी तवज्जोह चाहता हूं। सैकड़ों लोग जान से गये और लाखों बेघर हैं। वहां की हुकूमत पर चन्द अशार नज़र करता हूं--

बेदम हुए बीमार, दवा क्यों नहीं देते
तुम अच्छे मसीहा हो, शफ़ा क्यों नहीं देते
मिट जाएगी मख़लूक, तो इन्साफ़ करोगे
मुन्सिफ हो अगर तो हशर उठा क्यों नहीं देते

मग़रिबे बंगाल की वज़ीरे आला, हमारी दीदी ममता बनर्जी ने कहा है कि बंगाल, असम के पनाहगज़ीनों को दिल में जगह देंगी और हम लोगों का यह फर्ज़ है कि उन मज़लूमों, जिनके अपने उनसे बिछड़ गए हैं, को भरपूर रिलीफ मिले।

वाइस चेयरमैंन साहब, आपके जरिए मैं यह बात ऐवान की तवज्जो में लाना चाहता हूं कि बंगाल के जिला जलपाईगुड़ी सब डिवीजन अलीपुर द्वार में मोमिनपुरा और जसवन डांगा

[श्री मो. नदीमुल हक]

नामी रिलीफ कैम्प चल रहे हैं। ये दरअसल सेहरा में बाग़ का काम कर रहे हैं कि वहां के जो मज़लूम वहां आए हैं, उनको वहां सही मिकदार में रिलीफ दिया जा रहा है। ये लोग तो हालत सुधरने का इंतजार करै रहे हैं और अपने घर वापस जाने को तैयार थे, लेकिन जाता तशद्दुद की खबरों ने इनका हौसला पस्त कर दिया है और वे वहां रहने पर मजबूर हैं।

मैं ममता बनर्जी जी की बातो को दोहराता हूं कि असम के पनाहगज़ीनों की जानिब हमारा फर्ज़ है कि उनकी माकूल देखभाल की जाए। मैं यहां ज़ोर देकर कहूंगा कि काफी वक्त गुजर गया है और मजीद वक्त बरबाद नहीं किया जाए। इन पनाहगज़ीनों की बाज़आबादकारी, यानी रिहैबिलिटेशन, का काम फौरन जंगी पैमाने पर शुरू किया जाए। जानें जो जा चुकी हैं, वे तो वापस नहीं की जा सकती, फिर भी जहां तक मुमकिन हो, उनके जानी व माली नुकसान की पूरी तरह भरपाई की जाए, यानी उनको कम्पेंसेशन दिया जाए।

जुल्म की बात की क्या, जुल्म की औकात ही क्या।
जुल्म फिर जुल्म है, आगाज़ से अंजाम तलक।
खून फिर खून है, नौ सौ शक्लें बदल सकता है।
ऐसी शक्लें कि मिटाओ तो मिटाए न बने,
ऐसे शोले कि बुझाओ तो बुझाए न बने,
और ऐसे नारे कि दबाओ तो दबाए न मरे।

वाइस चेयरमैन साहब, मैं आखिर में कहूंगा कि जब आइंदा 15 अगस्त को लाल किला पर तिरंगा लहराएगा और हम गुनगुनाएंगे-"सारे जहां से अच्छा, हिन्दोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, यह गुलिस्तां हमारा.."। तो असम के लोगों के दिल पर क्या गुजरेगी, ज़रा सोचिए। वाइस चेयरमैन साहब, आज इस ऐवान से यह पैगाम जाना चाहिए कि ऐ असम के लोगो, तुम अपने दुख और दर्द में अकेले नहीं हो, बल्कि सारा मुल्क तुम्हारे साथ है।

सर, वज़ीरे आजम साहब यहां मौजूद हैं और वे खुद असम से हैं। मैं फिर एक बार दोहराउंगा कि रिहैबिलिटेशन और कम्पेंशेसन का काम वहां पर फौरी तौर से शुरू किया जाए। इसके साथ भी उनसे यह अपील है, बल्कि हमारे सारे बंगाल की अपील है कि वहां के लोगों की देखभाल फिर से की जाए।

सर, आखिर में मैं एक शेर कह कर अपनी बात खत्म करता हूं कि
मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना।
हिन्दी हैं हम, वतन है, हिन्दोस्तां हमारा।।

शुक्रिया।

†**جناب ندیم الحق (مغربی بنگال):** ایک د و جگہ نہیں، سارا بدن زخمی ہے، درد بیچارہ پریشاں ہے کہ کدھر سے اٹھے۔

وائس چیئرمین سر، سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے میڈن اسپیچ کی اجازت دی گئی ہے --(مداخلت)--

† Transliteration in Urdu Scripts.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): I will go through the record. Please don't worry.

جناب ندیم الحق : آسام کا تشدّد بہت بڑا سماجی تصادم ہے، ہاں، وہاں بوڈو مارے گئے ہیں، ہاں، وہاں مسلمان مارے گئے ہیں، لیکن سب سے ضروری بات یہ ہے کہ وہاں انسان مارے گئے ہیں اور انسانیت رسوا و غارت ہوئی ہے۔ ایک شعر یہاں عرض کرتا ہوں :-

جنگ مشرق میں ہو یا مغرب میں،
نسل آدم کا خون ہوتا ہے

مظلوم انسانوں پر ظلم ہو رہا ہے اور انتظامیہ کی خاموشی پر آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ سینکڑوں لوگ جان سے گئے اور لاکھوں بےگھر ہیں۔ وہاں کی حکومت پر چند اشعار نظر کرتا ہوں

بےدم ہوئے بیمار، دوا کیوں نہیں دیتے
تم اچھے مسیحا ہو، شفا کیوں نہیں دیتے
مٹ جائے گی مخلوق، تو انصاف کروگے
منصف ہو اگر تو حشر اٹھا کیوں نہیں دیتے

مغربی بنگال کی وزیر اعلی، ہماری دیدی ممتا بنرجی نے کہا ہے کہ بنگال، آسام کے پناہ گزینوں کو دل میں جگہ دیں گے اور ہم لوگوں کا یہ فرض ہے کہ ان مظلوموں، جن کے اپنے ان سے بچھڑ گئے ہیں، ان کو بھرپور ریلیف ملے۔

وائس چیئرمین صاحب، آپ کے ذریعے میں یہ بات ایوان کے توجہ میں لانا چاہتا ہوں کہ بنگال کے ضلع جل-پائی-گڑی، سب-ڈویژن علی پور دوار میں مومن پورہ اور جسوندانگا نامی ریلیف کیمپ چل رہے ہیں۔ یہ دراصل صحرا میں باغ کا کام کر رہے ہیں کہ وہاں کے جو مظلوم وہاں آئے ہیں، ان کو وہاں صحیح مقدار میں ریلیف دیا جا رہا ہے ۔ یہ لوگ تو حالت سدھرنے کا انتظام کر رہے ہیں اور اپنے گھر واپس جانے کو تیار تھے، لیکن تازہ تشدّد کی خبروں نے ان کا حوصلہ پست کر دیا ہے اور وہ وہاں رہنے پر مجبور ہیں۔

میں ممتا بنرجی کی باتوں کی دوہراتا ہوں کہ آسام کے پناہ گزینوں کی جانب ہمارا فرض ہے کہ ان کی معقول دیکھ بھال کی جائے۔ میں یہاں زور دیے کر کہوں گا کہ کافی وقت گزر گیا ہے اور مزید وقت برباد نہیں کیا جائے۔ ان پناہ گزینوں کی بازآبادکاری، یعنی ریہیبلیٹیشن، کا کام فورًا جنگی پیمانے پر شروع کیا جائے۔ جانیں تو جا چکی ہیں، وہ تو واپس نہیں کی جا سکتیں، پھر بھی جہاں تک ممکن ہو، ان کے جانی و مالی نقصان کی پوری طرح بھرپائی کی جائے، یعنی ان کو کمپنسیشن دیا جائے۔

ظلم کی بات ہی کیا، ظلم کی اوقات ہی کیا۔
ظلم پھر ظلم ہے، آغاز سے انجام تک
خون پھر خون ہے، نو سو شکلیں بد سکتا ہے
ایسی شکلیں کہ مٹاؤ تو نہ بنے،
ایسے شعلے کہ بجھاؤ تو بجھائے نہ بنے،
اور ایسے نعرے کہ دباؤ تو دبائے نہ مرے۔

وائس چیئرمین صاحب میں آخر میں کہوں گا کہ جب آئندہ 15 اگست کو لال قلعہ پر ترنگا لہرائے گا اور ہم گنگنائیں گے

سارے جہاں سے اچھا، ہندوستاں ہمارا،
ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔

تو آسام کے لوگوں کے دل پر کیا گزرے گی، ذرا سوچئے۔ وائس چیئرمین صاحب، آج اس ایوان سے یہ پیغام جانا چاہئے کہ اے آسام کے لوگوں، تم اپنے دکھ اور درد میں اکیلے نہیں ہو، بلکہ سارا ملک تمہارے ساتھ ہے۔

سر، وزیر اعظم صاحب یہاں موجود ہیں اور وہ خود آسام سے ہیں۔ میں پھر ایک بار دوہراؤں گا کہ ریہیبلیٹیشن اور کمپنسیشن کا کام وہاں پر فوری طور سے شروع کیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی ان سے یہ اپیل ہے، بلکہ ہمارے سارے بنگال کی اپیل ہے کہ وہاں کے لوگوں کی دیکھ بھال پھر سے کی جائے۔

سر، آخر میں، میں ایک شعر کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ

مذہب نہیں سکھاتا، آپس میں بیر رکھنا
ہندی ہیں ہم وطن ہیں، ہندوستاں ہمارا۔

شکریہ۔

श्री नरेश अग्रवाल (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष जी, मुझे अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद।

असम में जो हुआ, उसकी मैं भर्त्सना करता हूं और मेरा दल भी उसकी भर्त्सना करता है। मैं तो प्रधान मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि सिर्फ असम ही नहीं, देश के किसी भी भग में अगर ऐसी कोई भी घटना हो, तो केन्द्र सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि वह उस घटना को गम्भीरता से ले। मुझे दुख है कि राज्य सरकार को जितनी गम्भीरता और तत्परता दिखानी चाहिए थी, जो मीडिया में आया, मैं तो तब असमें नहीं था, लेकिन वह बहुत अच्छा नहीं दिखाई दिया। ऐसा क्यों हुआ, यह तो वहां के लोग ही बता सकते हैं। इस पर मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन प्रधान मंत्री जी, मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि नॉर्थ-ईस्ट बारूउ के एक मुहाने पर खड़ा हुआ है। मैं अभी फाइनांस कमेटी की ओर से शिलांग गया था। गोवाहाटी gateway of North-East है, जो seven sisetrs of country कहलाते हैं। अगर वहां के लोगों का विश्वास हमारे प्रति हटता चला गया--मैं थोड़ी-सी बात कर रहा हूं। मैं बहुत ज्यादा नहीं कह रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि नॉर्थ-ईस्ट कश्मीर बने, लेकिन अगर वहां के लोग हमारे पड़ोसी मुल्क को अपने नजदीक समझेंगे और हमसे दूरी बनाने की बात करेंगे, तो हमें इसको बहुत गम्भीरता से लेना चाहिए। मेरे ख्याल से नॉर्थ-ईस्ट का सबसे बड़ा स्टेट अरुणाचल प्रदेश है और उसके बाद असम आता है। आज अरुणाचल की जो स्थिति है, वह आपसे छिपी नहीं है। आज अरुणाचल में अगर हम as a tourist जाना चाहें, तो कहीं-न-कहीं हम अपने को असुरक्षि समझने लगते हैं।

अगर नॉर्थ-ईस्ट की यही स्थिति बनी रही, प्रधान मंत्री जी, तो देश के सामने फिर एक गंभीर होगी। इसके लिए केन्द्र सरकार सख्त रवैया नहीं अपनाती है? ग्रिड की पॉवर फेल हो सकती है, लेकिन सरकार की पॉवर फेल नहीं हो सकती है। ग्रिड की पॉवर तो फेल हो गई, देश में दो बार ग्रिड की पॉवर फेल हुई, लेकिन अगर सरकार की पॉवर फेल हो गई, तो?

राजनीति में बहुत खामोशी भी अच्छी नहीं होती है। खामोशी को हां पक्ष वाला अपने हक में ले लेता है और ना पक्ष वाला अपने हक में ले लेता है, यानी दोनों पक्ष उसको अपने हक में ले लेते हैं और इससे स्थिति बड़ी भयावह हो जाती है। आज केन्द्र सरकार की चुप्पी में ही अन्ना हजारे जैसे लोगों को मौका मिल गया, कल एक बाबा बैठने जा रहे हैं, उनको मौका मिल गया। हमने तो हर दम खुलेआम इस चीज का विरोध किया कि चंद लोग इकट्ठा हो जाएं और देश के कानून बनाने की बात करने लगे, हमारा देश इससे सहमत नहीं है। राजनीतिक लोग देश की समस्या को राजनीतिक तरीके से निपटाएं। हो सकता है कि कुछ लोग यहां पर उन्हीं चीजों से सहमत हो, जो भगवान के नाम पर सत्ता में पहुंच सकते हैं। वे सोचते हैं कि शासद इसी के सहारे हम सत्ता में पहुंच जाएं, लेकिन हम इससे बिल्कुल सहमत नहीं हैं, क्योंकि राजनीतिक व्यक्तियों की बहुत मजबूरी होती है। हम राजनीतिक लोगों को भिन्न-भिन्न परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, हमें तो खुशी है कि अब वे लोग भी राजनीति में उतर रहे हैं। कम से कम उनको पता लगेगा कि राजनीति क्या है। हमारे उधर तो कहा जाता है कि अगर अपनी पिछली तीन पीढ़ी के बारे मालूम करना हो, तो एक चुनाव लड़ लो, विपक्ष वाले खुद ही सब कुछ बता देंगे। थोड़े दिन बाद यही सब चीजें खुद देखेगा।

यह खाली असम की समस्या नहीं है, बल्कि आज विदेश में भी जो हिन्दुस्तानियों के

[श्री नरेश अग्रवाल]

साथ हो रहा है, अमेरिका में जो सिखों के साथ हुआ, उसके बारे में आज ही बात हो रही थी, आस्ट्रेलिया में जो हिन्दुस्तानियों के साथ हो रहा है, कनाडा में जो हो रहा है, दुबई में जो हो रहा है, आज देश के विभिन्न हिस्सों में जहां हम सुनते हैं, वहां हिन्दुस्तानियों के साथ ज्यादती हो रही है, लेकिन हम चुप हैं। हम रोज पाकिस्तान से बात करते हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं होता है। अभी पाकिस्तान के टीवी पर आया कि वहां अल्पसंख्यकों का खुलेआम धर्म परिवर्तन किया गया और उसको टीवी पर दिखाया गया, लेकिन हम चुप बैठे हैं, हम बोल ही नहीं सकते हैं। अगर हम अपने लोगों के बचाव के लिए ठोस कदम नहीं उठाते हैं, अगर हम उनके बचाव के लिए कार्रवाई नहीं करते हैं तो यह हमरी कमजारी कहलाएगी। यह कमजोरी उचित नहीं है और मैं इसका पक्षधर नहीं हूं।

मैं खुलेआम इस बात को कहता हूं और इसका पक्षधर भी हूं कि सत्ता में सता के तरीके से चलें। साम, दाम और दंड के लिए सत्ता है, सत्ता खामोशी के लिए नहीं है, सत्ता कोई साधु के लिए नहीं है, सत्ता है देश के हित के लिए और मैं आपसे कहूंगा, हम सब लोग इस बात के पक्ष में हैं। ठीक है, अभी आलोचना हो रही है, सुबह तो श्रद्धांजति अर्पित हो रही थी, लेकिन अभी उसका राजनीतिकरण हो गया। जब सदन शुरू हुआ, तब असम में जो बाढ़ से मारे गए, असम में जो इस हिंसा में मारे गए, सबके लिए हम लोग श्रद्धांजलि दे रहे थे, लेकिन अभी उसका राजनीतिकरण हुआ। लेकिन, अगर देश के हित में कोई निर्णय लेंगे, तो यह सदन आपके साथ खड़ा होगा। हम सब आपके साथ खड़े होंगे, कम से कम कोई निर्णय तो लीजिए। यह न हो कि हम चौराहे पर हम लोग नंगे किए जाएं और सदन चुप रहे। राजनीतिक व्यक्तियों के प्रति अपशब्द कहे जाएं और हम अपने अधिकरों का इस्तेमाल सिर्फ चुप रह कर कर लें, सिर्फ चुप रहना राजनीति में बहुत अच्छा नहीं होता है, बल्कि राजनीति में पलट कर जवाब देना बहुत अच्छा होता है और मैं प्रधान मंत्री जी से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि असम की समस्या को गंभीरता से लेना चाहिए।

जो सबने कहा, वहीं मैं भी कहता हूं कि अगर देश में घुसपैठ नहीं रोकी गई, तो देश की आबादी तेजी वे बढ़ती चली जाएगी। अगर इतनी तेजी से आबादी बढ़ेगी, तो हम बाहर के कितने लोगों को खिलाते चले जाएंगे? आखिर यह ठेका हम लोगों का तो नहीं है, यह सब ठेका हिन्दुस्तान ने नहीं ले रखा है। जैसे हमने कश्मीर में घुसपैठ रोकी, वैसे ही हम वहां उस बॉर्डर को क्यों नहीं सीज कर सकते हैं? हमें उस बॉर्डर को भी सीज करना चाहिए, लेकिन जो देश में रह रहा है, जो देश में आ गया, उसकी रक्षा करना हमारा परम कर्त्तव्य है, चाहे वह हिन्दू हो, चाहे वह मुसलमान हो, चाहे सिख हो या चाहे ईसाई हो। यह हम सबका कर्त्तव्य है। मैं तो आपसे इतना कहूंगा कि इस पर चिंता कीजिए, विचार कीजिए कि आखिर ऐसा असम में क्यों हुआ और इसका स्थाई समाधान क्या होगा? आज हम मुख्य मंत्री को दोष दे दें, वहां की सरकार को दोष दे दें, वहां की व्यवस्था को दोष दे दें, तो खाली दोष देने से कुछ नहीं होता है। दोष तो कायर लोग देते हैं, जो हिम्मत वाले होते हैं, वह स्थाई समाधान की बात करते हैं और हम अंत में इतना ही कहेंगे,

"न हिन्दू हैं हम, न मुसलमान हैं हम,

इंसान की औलाद हैं, इंसान हैं हम।"

बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री विश्वजीत दैमारी: वाइस चेयरमैन जी, असम में जो वायलेंस हुई है, उस विषय पर आज यहां चर्चा हो रही है। मैं उसी जगह, यानी बोडोलैंड टेरेट्रियल काउंसिल से हूं।

सर, सबसे पहले मैं यह बताना चाहता हूं कि वह घटना शुरू कैसे हुई, क्योंकि इस घटना की चर्चा यहां बहुत ही नई-नई समस्याओं से जोड़ कर की गयी है। हम चाहते हैं कि इस मामले में इस पार्लियामेंट से सहायता मिले ताकि वहां पर फिर से शान्ति स्थापित हो। जो विक्टिम्स फैमिलिज़ और लोग हैं, वे एक साथ रह सकें, इसके लिए आप लोगों की सहायता बहुत ही जरूरी है। इसके लिए वहां की जो सत्य घटनाएं हैं, उनको जानना भी बहुत जरूरी है। वहां पर जो इन्सर्जेन्सी या एक्सट्रिमिस्ट्स की प्रॉब्लम है, उसको लेकर इस घटना की शुरूआत हुई थी। वहां हर समय किडनैपिंग होती है, एक्सटॉशर्न होता है, किलिंग होती है और ऐसा वहां होता रहता है। वहां सिर्फ मुस्लिम, बोडो, इसमिज़ या बंगाली ही नहीं, बल्कि वहां के सभी साधारण आम आदमी भी एक्सट्रिमिस्ट्स के विक्टिम्स हैं। बोडोलैंड के सारे इनाकों में एक्सट्रिमिस्ट्स एक्टिव हैं। वहां नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (उनडीएफबी) के दो ग्रुप्स हैं, एक गोबिन्द बसुमतारी का ग्रुप और दूसरा रंजन दैमारी का ग्रुप। यह सबको पता है कि वहां अल्फा, मुस्लिम्स का मुस्लिम यूनाइटेड लिबरेशन टाइगर्स ऑफ असम (मल्टा) और आदिवासियों का कोबरा मिलिटैंट्स एवं बिरसा कमाण्डो फोर्स जैसे दो-तीन एक्सट्रिमिस्ट्स ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं। वहां पर राजबोंगशी कम्युनिटी का कामतापुर लिबरेशन ऑर्गेनाइज़ेशन (केएलओ) है, जो कामतापुरी की डिमांड कर रहे हैं। इसी तरह के वहां कई अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं, जिनकी हर समय कुछ न कुछ एक्टिविटी होती रहती है। वहां पर मुस्लिम भाइयों की ऑल असम माइनॉरिटीज़ स्टेडेंट्स युनियन (आमसू) है और बोडोलैंड इलाके में ऑल बोडोलैंड माइनॉरिटीज़ स्टूडेंट्स यूनियन है। जब वहां मुस्लिम्स के साथ किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन या कभी-कभी किलिंग्स की घटनाएं होती हैं, तो वे लोग यह आवाज़ उठाते हैं कि मुस्लिम लोगों को वहां पर निरापदता देनी चाहिए। इस कारण, वे लोग सरकार से यह मांग करते आ रहे हैं कि हमको निरापदता दी जाए और उन लोगों को निरापदता देने में सरकार कामयाब नहीं हुई। Unfortunately, लास्ट मोमेंट आते-आते यह हुआ कि बोडोलैंड टेरेट्रियल काउंसिल वहां के चार डिस्ट्रिक्ट्स में हैं-कोकराझार, चिरांग, उदलगुड़ी और बाकसा। इन चार जिलों में बोडोलैंड टेरेट्रियल काउंसिल के बारे में अभी हमारे तिवारी साहब बता रहे थे। हगरामा मोहिलरी, जो बोडो लिबरेशन टाइगर्स का चेयरमैन था, वह ऐग्रीमेंट करने के बाद, आर्म्स सरेण्डर करने के बाद और पॉलिटिकल पार्टी बनाने के बाद इलेक्टैड गवर्नमैंट चला रहा है। वह वहां का डेवलपमेंट काउंसिल चला रहा है और इसी कारण मुस्लिम लोगा सोचते हैं कि अगर वह चाहे, तो उन्हें निरापदता दे सकता है, लेकिन unfortunate बात यह है कि बोडोलैंड टेरेट्रियल आउंसिल में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल करने की क्षमता नहीं है, वहां पर पुलिस के ऊपर कोई पावर नहीं है। वहां पर जो डिप्टी कमिश्नर है, वह बोडोलैंड टेरेट्रियल काउंसिल के अंदर नहीं आता है, जो लॉ एंड ऑर्डर को देखता है। वहां मोहिलरी साहब की जो गवर्नमैंट है, वह निरापदता के मुद्दे पर सजेशन देने के सिवाय कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि वह खुद अपनी निरापदता के लिए और इस तरह के हादसों को रोकने के लिए गवर्नमैंट होते हुए भी समय-समय पर धरने देती है कि हमको sufficient force चाहिए, हमारे बोडोलैंड एरिया में सिक्योरिटी को टाइट किया जाना चाहिए। लेकिन, हमारे मुस्लिम्स भाइयों को यह पता नहीं है

[श्री विश्वजीत दैमारी]

कि एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था के अन्दर क्या है। उसके लिए उन लोगों को यह गलतफहमी है कि ये हगरामा के कारण हो रहा है और चूंकि हगरामा बोडो है, इसलिए वे लोग बोडो जाति के ऊपर हर समय कुछ न कुछ मंतव्य करते हैं।

सर, जून-जुलाई के महीने में अचानक ही बहुत नई-नई घटनाएं होने लगीं। सबसे पहले नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट (एनडीएफ) ने एक राजबोंगशी परिवार को कुछ लाख रुपयों की मांग करते हुए एक एक्सटोर्शन नोटिस दिया था। उन्होंने पुलिस को बताया कि हमें एक्सटोर्शन नोटिस मिला है, अब हमें क्या करना चाहिए? पुलिस ने उन लोगों के साथ प्लान करते हुए कहा कि आप उन लोगों को बुलाइये, हम उन्हें पकड़ते हैं और एक दिन पुलिस ambush में रही और उनको बुलाने के लिए कहा। तब एन.डी.एफ.बी. से कहा गया कि आपका पैसा तैयार है, आप आकर ले जाओ। इसके बाद जब वहां दो लड़के मोटरसाइकिल से पैसे लेने आए, तो वहां पुलिस को देख कर वे भागने लगे, तब पुलिस ने उन पर फायर किया।

बाद में पता लगा कि वे लड़के मुस्लिम थे। लेकिन वह डिमांड नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड के आर्गनाइजेशन का था, जिसने extortion notice दिया था। लेकिन बतलाना मुश्किल हो गया, क्योंकि वे दोनों मर गये थे। एन0डी0एफ0बी0 के नाम पर सिर्फ पैसा लेने के लिए वे लोग ब्लैकमेल किया है या नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड ने उन लोगों को इस्तेमाल किया है पैसा कलेक्शन करने में। दोनो में से एक हो सकता है। तब ज्यादा विद्रोह हो गया All Minority Student Union (AMSU) की तरफ से कि वहां पर दो इन्नोसेंट मुस्लिम लड़कों को मार डाला है। इसके बाद एक दिन स्कूल में सर्वशिक्षा अभियान का काम चल रहा था, जहां पर मुस्लिम लेबर थी, उन लोगों को भी गोली मारा गया जिससे दो मर गए और दो इन्जर्ड हो गए। मुस्लिम लोग समझने लगे कि इनको एन0डी0एफ0बी0 ने ही मारा है, एन0डी0एफ0बी0 बोडो है, इसलिए मह लोग बोडो के साथ नहीं रहेंगे और उनके साथ युद्ध करना चाहिए। हजारों लोगों ने थाने का घेराव किया जिससे बहुत टेंस हुआ और वहां पर बात करके बिगड़ती स्थिति को संभाला गया। इन्जर्ड लोगों ने बतलाया कि यह आदिवासी एक्स्ट्रीमिस्ट थे बोडो नहीं है, एक्च्युअली वह एन0डी0एफ0बी0 नहीं है। इसके बाद दोनों मरने वाले आदिवासियों को पकड़ा भी गया, जो मारने में इंवोल्व्ड थे। इसके बाद एक दूसरी घटना हुई, एक ब्रिज का काम चल रहा था जहां आकर गोलीबारी की गई। वहां के कांट्रेक्टर को पहले extortion notice दिया था और फिर बाद में भी पैसा नहीं मिला। इस कारण कैम्प में जो लेबर वगैरह रहती है, उन पर गोलीबारी कर दी। इस कारण दो लोग मर गए। फिर हल्ला हो गया कि इनको एन0डी0एफ0बी0 ने मारा है। इस वजह से गाड़ी वगैरह तोड़ी गई तथा उनको जलाया गया। पुलिस इंवेस्टिगेशन में निकला कि यह KLO-Kamatapur Liberation Organisation ने किया है। पुलिस ने कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया। इसके बाद लास्ट मोमेंट में एक घटना और हुई कि दो मुस्लिम लोगों को गोली मार दी गई। वह police constable था और कुछ arms smuggling के कारण वह सस्पेंशन में था तथा इसने इंसीडेंट होने के चार-पांच दिन पहले फिर से ड्यूटी में जॉइन भी कर लिया था। इसके बाद पुलिस ने इंवेस्टिगेशन करके बतलाया कि इनके स्मगलिंग के कारोबार में किसी से झगड़ा होने के कारण ऐसा हुआ है। इसलिए यह मामला individual है तथा इसमें किसी एक्सट्रीमिस्ट का कोई हाथ नहीं है। उसी रात इन्जर्ड पर्सन को कोकराझार में Runath Brahma Civil Hospital में लाया

गया था। कोकराझार पुलिस स्टेशन के एक मिलोमीटर दूरी पर जयपुर गांव है। उस गांव में बोडो और मुस्लिम एक साथ रहते हैं। जो लोग इन्जर्ड पर्सन को अस्पताल में ले गए थे, उन लोगों ने वहां बोडो के घरों में और लोगों को पत्थर वगैरह मारा तथा उनके खिलाफ कुछ स्लोगन देकर चले गए। उस घटना को लेकर यहां बोडो और मुस्लिम दोनों टेंस हो गए। वह 19 तारीख की घटना थी, फिर next दिन ईवनिंग में 20 तरीख को जयपुर गांव में ऐसा हल्ला वगैरह हुआ कि किसी ने गांव में आकर blank fire किया है। पुलिस को सूचना मिलने पर गांव में पुलिस आ गई। उसी समय चार लड़के मोटर साईकिल से आ रहे थे जिनको पुलिस ने रोक लिया तथा उनको थाने में ले जाने की कोशिश की।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Now, please try to conclude. दो मिनट और ले लीजिए।

श्री बिश्वजीत दैमारी: मै घटना को बतला रहा हूं कि वह कैसा घटित हुई। तो वहां के कुछ मुस्लिम लोगों ने बोडो लोगो को बतला दिया कि आपके कुछ लड़कों को पुलिस ने रोक रखा है। और पब्लिक वहां पर बहुत tense है। वह किसी भी टाइम उन लोगों को मार सकती है। आप किसी पुलिस ऑफिसर को बोलकर उन लोगों को लेकर जाइए। तब वहां के Superintendent of Police को बताया गया कि जयपुर में कुछ लड़को को पुलिस ने रखा और उनको पब्लिक मारना चाहती है। क्या आप इस बारे में जानते हैं? तो वहां ड्यूटी पर जो आ0सी0 था, उसने एस0पी0 बता दिया कि व उनके हाथ में हैं। S.P. फिर से बता दिया कि हां, लड़के पुलिस के हाथ में हैं और tense होने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर 10-15 मिनट बाद खबर आई कि उन चार लड़कों को पुलिस के हाथ से लेकर वहां मार दिया गया है। इस कारण रात में पूरा माहौल tense हो गया। फिर यह घटना होने के बाद 21 तारीख से tension शुरू हो गया और रैली वगैरह निकली कि पुलिस की presence में उनको मार दिया गया। उसी दिन शाम को, जाहां एक मुस्लिम और बोडो गांव साथ-साथ थे, वहां के लोग शांति कमेटी बनाने के लिए मीटिंग कर रहे थे, ऑल बोडो मुस्लिम स्टूडेंट्स यूनियन की तरफ उन पर आक्रमण किया गया। वहां दो बोडो महिलाओं को मार डाला गया और उनके घरों को जला दिया गया। साथ ही कुछ लोग injured भी हुए। इसके बाद last moment में situation uncontrolled हो गयी। फिर वहां प्रोपेगेंडा भी चला कि उधर से मुस्लिम ऐसे अटैक कर रहे हैं। बोडो लोगों पर अटैक हो रहा है और बोडो लोग भी उतर रहे हैं। तो उसी दिन से यह situation 26 तारीख तक चली आ रही है। तो यह मूल घटना है और मैं यहां क्लैरीफिकेशन देना चाहूंगा कि बोडो लैंड को लेकर इसमें कोई गलतफहमी नहीं है कि मुस्लिम लोगों को भगाने के लिए यह किया जा रहा है या बोडो लैंड काउंसिल का इसमें हाथ है या बोडोज का इसमें डायरेक्ट हाथ है। Actually ऐसा कुछ नहीं है जबकि ऐसी कहानी बनायी जा रही है। दूसरा, वहां विदेशी की समस्या है। इस बारे में सभी को पता है। इस बारे में हमको पॉलिसी डिसीजन लेना है। इस समस्या का समाधान करने के लिए जब तक हमारी सरकार एक अच्छी पॉलिसी नहीं बनती, तो इस तरह की समस्या पैदा होती रहेगी। मैं चाहता हूं कि सरकार इस समस्या के समाधान के लिए व्यवस्था करे। इसे delay नहीं किया जाए। अभी Border fencing की बात बतायी गयी है। West Bengal में बॉर्डर फेंसिंग नहीं हो

[श्री विश्वजीत दैमारी]

रही है। West Bengal Govt. की तरफ से जमीन नहीं दी गयी है। इसके लिए केन्द्र सरकार जल्द West Bengal Govt. से बात करे ताकि वह फेंसिंग के लिए जमीन दे। उसकी व्यवस्था की जानी चाहिए, लेकिन अगर हम ऐसे ही बात करते रहेंगे, तो कुछ भी होने वाला नहीं है।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Please conclude it now.

श्री बिश्वजीत दैमारी: वहां शांति के लिए आप लोगों का cooperation चाहिए। वहां मुस्लिम और बोडो लोग वापस अपने गांवों को जाना चाहते हैं। उसमें दोनों तरफ के समान लोग मरे हैं। उसमें उन लोगों को रिलीफ की भी जरूरत है। इस तरह से सारी situation वहां बिगड़ी हुई है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अगर जरूरत पड़े तो पार्लियामेंट की तरफ से भी एक delegation जाना चाहिए और दोनों तरफ के लोगों को समझाना चाहिए। इस बारे में कोई गलतफहमी पैदा नहीं होनी चाहिए। वहां मुस्लिम, हिंदू जैसी बात नहीं है। वहां पर कोई-न-कोई घटना होने के बाद फायदा उठाने के लिए और कोई पुरानी समस्या उसके साथ जुड़ी हुई है, उस समस्या को जोड़कर कोई-न-कोई comment आते रहेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि बोडो लैंड की समस्या को हल करके वहां शांति का परिवेश लाने में help की जानी चाहिए। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वहां लोगों को फिर से बसाने के लिए relief and rehabilitation की व्यवस्था जल्द होनी चाहिए।

श्री तारिक अनवर (महाराष्ट्र): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं कि समय का अभाव है, इसलिए मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चहता। हमारे पूर्ववक्ताओं ने असम के कोकराझार में घटी घटना के बारे में विस्तार से सारी बातों को बताया है। मेरा मानना है कि आजादी के एक लम्बे समय के बाद भी अगर हमारे देश में इस तरह की घटना होती है, तो उसके लिए हम सबको उसके लिए चिंता करने की आवश्यकता है। खास तौर पर जब हम सांप्रदायिक सद्भाव की बात करते हैं, एकता और मिलजुलकर चलने की बात करतें हैं और जब वहां इस तरह की कोई घटना हो जाती है तो इससे समाज के अंदर जो आपसी मन-मुटाव पैदा होता है, वह दूरगामी होता है और इसका नुकसान आने वाले समय में हमें उठाना पड़ता है।

मैं समझता हूं कि इस बात से पूरा सदन सहमत होगा कि जो कुछ भी वहां घटा है, तो भी घटना वहां घटी है, वह निंदनीय है और उससे अभी लोगों को दुख पहुंचा है, पूरे देश को दुख पहुंचा है। हमें इस ओर गंभीरता से देखना चाहिए, इसकी जड़ में जाना चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में आगे ऐसी घटना फिर से न घटे। यह एक सच्चाई है कि चाहे किसी समुदाय के लोग हो उनको उस जगह पर, उस क्षेत्र में एक साथ रहना है अच्छे पड़ोसी बन कर रहना है। इसलिए हमें एक ऐसा माहौल बनाने की जरूरत है, जिससे उनमें आपस में मतभेद के बजाय एक मेल-मिलाप की भावना बने। वहां जो घटना घटी, जो नुकसान हो चुका, वह तो सामने है, मगर आगे ऐसी घटना भविष्य में न घटे उसके उपाय करने की आवश्यकता है।

उपसभाध्यक्ष जी, जैसा माननीय सदस्यों ने का कि चार लाख से ज्यादा लोग वहां शरणार्थी कैम्पों में गए हैं। मैं समझता हूं कि आजादी के बाद से देश में शायद ही कहीं ऐसी घटना घटी हो कि इतनी बड़ी संख्या में लोग अपने गांव, अपने घरों को छोड़कर शरणार्थी

कैम्पों में जाने के लिए मजबूर हूए हों। अब यह भी एक अच्छी खबर आई है कि लोग धीरे-धीरे शरणार्थी कैम्पों से अपने घरों को, अपने गांव को वापिस होने लगे हैं। मैं समझता हूं कि वे तभी वापिस होना चाहेंगे, जब उनमें पूरी तरह से सुरक्षा की भावना आएगी कि वह वहां सुरक्षित रहेंगे। इसके लिए वहां के स्थानीय एडमिनिस्ट्रेशन को उनको यह विश्वास दिलाना पड़ेगा कि उनके लिए सुरक्षा की पूरी व्यवस्था है, उनकी जान-माल, उनकी आबरू की पूरी व्यवस्था है और तभी लोग अपने-अपने गांव में, अपने-अपने घरों में वापिस जाना चाहेंगे। अब केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के सामने जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वह यह है कि उन लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था हो, यानी उनके रीहैब्लिटेशन का काम हो ताकि, वहां लोग अपने-अपने घरों में, अपने-अपने गांव में वापिस जा सकें। इसके लिए सरकार की तरफ से जो उपाय किए जा रहे हैं, मैं समझता हूं कि वे ठीक हैं, लेकिन उनको और तेजी से करने की आवश्यकता है। जहां तक मरने वालों के आश्रितों को जो मुआवजे दिए गए हैं, मैं समझता हूं कि उसको बढ़ाना चाहिए, वैसे तो जान की कोई कीमत नहीं होती है, लेकिन कम से कम उनको दस लाख रुपए का मुआवजा देना चाहिए, जो लोग सीरियसली इन्जर्ड हुए हैं, उनको लगभग दो लाख का मुआवजा मिलना चाहिए और जिनको छोटी-मोटी इन्जूरी हुई है उनको भी पचास हजार की सहायता सरकार की ओर से मिलनी चाहिए। फिर जैसे जो मकान बर्बाद कर दिए गए हैं, जला दिए गए हैं, उनको फिर स बनाने की व्यवस्था उनके लिए होनी चाहिए, तभी लोग विश्वास करेंगे कि सरकार ने उनके पुनर्वास की पूरी व्यवस्था की है।

उपसभाध्यक्ष जी, यहां प्रधान मंत्री जी मौजूद हैं वे स्वयं असम से आते हैं, उन्हें वहां के बारे में सारी जानकारी है। वहां की समस्या के सुधार के लिए हम जितनी जल्दी कदम उठाएं, उतना अच्छा है। हम समझते हैं कि वहां जो हमारी विफलता रही है, वह इंटेलीजेन्स की रही है और वहां की जो स्थानीय पुलिस या वहां का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी रही है। जाहिर है कि वहां जो बाहर से पैरा-मिलिटरी फोर्स या आर्मी को बुलाया गया, वहां बहुत ही जरूरी था, आवश्यक था, क्योंकि वहां की स्थानीय एडमिनिस्ट्रेशन की विफलता सामने दिखाई पड़ रही थी। यह जरूरी था कि वहां पर केन्द्र की सहायता दी जाए। वहां प्रधान मंत्री जी भी जा चुके हैं, हमारे होम मिनिस्टर भी वहां गए थे और जाहिर है कि इनके वहां जाने के बाद से कुछ चीजें नियंत्रण में आई हैं, लेकिन अभी भी घटना घट रही है। कल के अखबारों में हमने देखा, आज भी वहां से जो हमारे पास खबरें आ रही हैं, लोगों में अभी भी एक टेन्स बना हुआ है, एक असुरक्षा की भावना बनी हुई है, जिसको दूर करने की आवश्यकता है। जितनी जल्दी हम इसको ठीक करेंगे मैं समझता हूं कि वहां उतनी जल्दी शांति लाने में हमें मदद मिलेगी। मैं यही उम्मीद करता हूं कि सरकार इस ओर ध्यान देगी।

DR. V. MAITREYAN: Sir, the recent large-scale violence in Assam, particularly the three districts of Kokrajhar, Darrang and Dhubri in which hundreds have been killed and lakhs have been rendered homeless and refugees in their own motherland, is really shocking and condemning. On behalf of my party, I offer our sincere and heart-felt condolences to the bereaved families. The hon. Prime Minister has visited the affected areas and I urge upon him to see that the relief and rehabilitation measures are taken up on a war-footing.

[Dr. V. Maitreyan]

In fact, the agenda paper which has been circulated, erroneously mentions it as the incidents of communal, violence in Assam. The issue is not communal. It is not a Hindu *versus* Muslim issue. The issue is not even ethnic. The issue is, Indians *versus* foreigners. Is the country going to stand by its Indian citizenry or is it going to bail out the foreign infiltrators? That is the issue.

In this regard, I would like to bring to the attention of the House the Election Manifesto of our Party for the Lok Sabha Elections, 2009 in which we have mentioned, "A major problem India has been facing with regard to its neighbours is the porous Indo-Bangladesh border which has encouraged the infiltration of Bangladeshi nationals into the North-Eastern Region, particularly West Bengal and Assam. The UPA Government has not been able to complete the much expected border fencing and roads. As a result, infiltration by Bangladeshis has been continuing unabated and in such volumes that the infiltrators outnumber the locals in many districts of several States. This has understandably caused tremendous strain on the job market and resources in these areas, resulting in-considerable tension and unrest. Even the electoral and religious dynamics in these areas have changed considerably."

In fact, the issue of illegal Bangladeshi migration and a covert move to legalise it had been first noticed in Mangaldoi in Darrang district in a Lok Sabha by-election in 1978 when around 45,000 illegal migrants' names were found on the voters list. The first strike against this was kick-started on 8th June 1979, resulting in the massive 'Assam Agitation' led by All Assam Students' Union, AASU, against Bangladeshi infiltration from 1979 to 1985.

While it is too early to blame either side of the ethnic divide for the ongoing violence in Assam, the growing fear among the indigenous Bodo community of being swamped by illegal Bangladeshi migrants has to be taken seriously. Moreover, there is a general suspicion in Assam that most of the local political parties depend on the votes of these illegal migrants for their hold on power. A porous border, continued illegal immigration, nexus between Bangladesh-based terror outfits and extra regional forces with local militant groups, and arms trafficking across the border create a situation of distrust, anxiety and insecurity in volatile districts like Kokrajhar. But policy makers often tend to ignore such harsh realities of an ethnically volatile region and adopt an ad hoc strategy without a deeper understanding of the social and political contradictions existing on the ground. Even after 27 years of signing of the Assam Accord, the fence along the India-Bangladesh border has not been completed. Both the Central and the State Governments of the UPA have failed to check the flow of illegal migrants, upgrade the National Register

of Citizens, arrest arms traffickers, and deal with armed movements. Unless the social and political impact of land loss on ethnic communities of Assam due to unabated migration from Bangladesh is checked, Assam will continue to remain vulnerable to ethnic clashes, armed violence and communal tensions in the near future.

I urge upon the Central Government to tackle the situation on a war-footing. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Now, Shri Kumar Deepak Das.

SHRI KUMAR DEEPAK DAS: Sir, today, I want to make my observations on the issue of Assam.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Please be brief because your Party has already taken full time.

SHRI KUMAR DEEPAK DAS: Sir, I want to make my speech in Assamese.

*Honourable Vice-chairman, sir, my state Assam has been going through an unfortunate phase since some time now. First of all, there were devastating floods which inundated thousands of villages and destroyed the lives of lakhs of people. Then again, in the GS Road incident, in the middle of the Guwahati metropolitan city, a woman was tortured and publicly molested. In Shivsagar town a girl was raped by the security personnel.

Sir, very unfortunate incidents have been occurring in the entire state of Assam. Women are being harassed and insulted on the streets in the centre of Guwahati city. And, now, there is this issue involving the Bodos and other people. Lakhs of people are suffering due to the violent incidents occurring there. Losing their hearth and home, Lakhs of people had to take shelter in relief camps. Reportedly, more than 5 lakh people took shelter in the camps. More than a hundred were killed. Sir, the Chief Minister of Assam has referred to the situation more accurately than me. Yesterday he said that Assam is sitting over a volcano. The Bodoland is in fire. It is burning. But who is responsible for that? Certainly, not the people of Assam. Neither the Bodo people, nor the Muslims can be blamed for the problems. It is the Government of Assam who is responsible for the present situation there. It is also the Central Government who is responsible.

Sir, let us go to the roots of the problem, there are fourteen Tribal Belt Blocks in Assam. In those Blocks people were allowed to settle illegally. And to prevent this illegal settlement AASU started a Movement against that in 1974. We had 14 Charter

* English translation of the original speech in Assamese.

[Shri Kumar Deepak Das]

of Demands during that Movement demanding release of the Blocks from the illegal settlers. But the settlers were not removed. The tribal population in those areas did not get protection against those illegal settlers.

Sir, we had started an Agitation against illegal foreigners. At the end of our Movement there was an Accord. According to the Accord it was agreed upon that there will be identification, deletion, and deportation of those foreign nationals. Nothing has happened so far excepting a few detection. But the Muslims of Assam are not responsible for that. Neither the Bodos, nor the Assamese people are responsible. It is only the Central Government and the State Government who are responsible.

Sir, then we had the Bodo Movement. As an outcome of that Movement, by an agreement BTAD was formed in Assam. But unfortunately, some absolutely non-Bodo villages were also included in the BTAD outside the agreement. The Bodos and non Bodos were divided. Differences showed up among the inhabitants of the area. This had happened at the instance of the Government. The State and Central Government are responsible for that. Sir, in the recent case also, timely measures were not taken. The Chief Minister did not take adequate steps on time. On the other hand, putting the blame on the Central Government, he said that the Central Government is not helping out. "I am requesting for help, but they are not responding", he said. The Chief Minister is helpless. The Chief Minister of Assam says he is helpless, "I am not getting any help from the Centre" —the Congress Chief Minister of Assam complains against the Central Government. The CM belongs to the Congress Party, and the same Congress Party is in power in the Centre. Sir, if proper preventive measures had been taken in the BTAD at the first instance of violence then the situation would not have become so serious.

Sir, foreign nationals have been immigrating into Assam in many different ways. And because of this illegal immigration there have been problems in the State. The Central Government is a total failure in arresting those problems. One Hon'ble Member said that the AGP Government did not do anything during their tenure. Yes, the AGP was supposed to have taken responsibility for the people of Assam; for the people of India. The Congress Government is unable to do that. They want votes from those people coming from Bangladesh. Those people are used as vote banks by the Congress. Therefore, the Congress needs their help and so those people are allowed to stay on in Assam. That is the Congress' motto. And now they have been blaming us. Yes, we could not detect and deport the illegal foreigners because of IDMT Act. But, what is the Congress doing? How many foreign nationals are

identified, deleted, and deported from Assam by the present Congress government in power after abolishing of IDMT? The erstwhile AGP Government, the Bodos, the Muslims or the people of Assam are not responsible for not deporting the foreign nationals.

Sir, we are thankful to the different political parties of India for their solidarity with us. The CPI, CPM BJP, Shiv Sena and people from other parties are visiting Assam and showing their solidarity with the suffering people of the State. We also thank the Prime Minister and the Home Minister of India for visiting the affected people. But the Government has not taken any effective step to solve the problem. Everybody will agree with that. All the political parties will agree that the responsibility of providing security is with the Government. When they came into power in Assam the Congress Government came with the promise of giving protection to life and property of the people of Assam. But have they done that? The Chief Minister says there is a Third Force. A third power is involved in the incidents occurring in Kokrajhar. Who is it? Where is it? If there is any Third Force involved then what is the Chief Minister doing? What was his responsibility to check such Third Force? Should not he have prevented recurrence of such incidents? He did not do anything. The Government of Assam is a total failure today. The Government is indifferent towards dangerous and volite situation prevailing in the State.

Sir, one Hon'ble member said today that due to the disturbances in Kokrajhar running of trains was stopped for one day in Assam. It is totally wrong. He has misled the House. Trains were stopped for 3 days. He also misled the House saying NRC update is in progress in Assam. Let him tell us where it is working. In which district is it working? It is not working. It is inactive. And it is stopped by the State Government and the Central Government. We want that the problem of illegal immigration is solved permanently. All of us want that. Then, let us take a decision that in the next two years, after identifying and deporting the foreigners we will bring a permanent solution to this burning problem and free the State from the illegal immigration. Let us take a decision. I wish to request all those present here, who seriously want a permanent solution, to take a decision in the floor of the House. Again I must say this attack on Muslims in Assam has not occurred for the first time. It happened in 1950 when the Congress was in power. Then it happened again in 1983 under the Congress Rule. Again in 1995 there was communal disturbances during the Congress Rule. It all happened in a large scale. Thousands of Muslims were massacred. All these happened during Congress Rule. There was no communal disturbance when the AGP was ruling the State. When they were in power minorities

[Shri Kumar Deepak Das]

were not harassed. We can claim that with full faith. We want peace. The people of Assam want peace.

Sir, yesterday the Congress said they will demand CBI enquiry. We welcome that. But first let there be peace in the State. The atmosphere should be made peaceful. Let the people go home from the refugee camps. ..'.

I need a little more time, sir...

The people who are still in refugee camps should be given protection to go home. They are not getting security. The children in the camps are not getting food. They want food. The Government should take care of their food. The students can not go back to school because they do not have books. Everything is burnt. The Government should provide them with books. Atmosphere should be created to bring normalcy to BTAD. All of us here should consider this as our responsibility to bring normalcy there.

Sir, I want to say a few words about the communal harmony in Assam. There is no need to teach us communal harmony. I want to say something there is a place called Hajo in Assam. There is a Masjid and a Mandir side by side there.

Hindus and Muslims both visit the Masjid and the Mandir. You will not find such harmony anywhere else in India. People of India should learn about communal harmony from the people of Assam. Those who are talking about Third Force is saying that only to divide us the people of Assam. If they know of any such thing they should bring that force out to light and punish them. Sir, there is no real Government in Assam now. If there is any Government it should work as a Government. Efforts should be made to bring back peace to Assam. With these words, I thank you sir, for giving me time to speak.

MESSAGE FROM LOK SABHA

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report to the House the following message received from the Lok Sabha, signed by the Secretary-General of the Lok Sabha:-

> "I am directed to inform you that Lok Sabha, at its sitting held on Wednesday, the 8th August, 2012, adopted the following motion:-
>
> "That this House do recommend to Rajya Sabha that Rajya Sabha do appoint one member of Rajya Sabha to the Joint Committee to examine